Let's work for Mother Nature

पर्यावरण PERSPECTIVE

August- September 2021
Not For Sale

राष्ट्रीय आपदा

24 स्वयंसेवक संघ का सेवाधर्म

भारतीय संस्कृति

18 पर्यावरण में गाय का गोबर सहायक

Urban Forest

12 Vulnerabilities and Resilience

Stepwell

10 The Maha Story

CONTENTS

संपादकीय: Come September: साथ आएं और मुस्कुराएं	3
Ecology: Restoring in a holistic way	4
Ecosystem: Prevent, Halt and Restore	6
Masks: Saving Humans, Overburdening Ecosystem	8
Stepwell: The Maha Story	10
Urban Forest: Vulnerabilities and Resilience	12
Astrology: The Celestial Sphere	16
भारतीय संस्कृति: पर्यावरण में गाय का गोबर सहायक	18
जल ही जीवन है: दम तोड़ती नदियों को बचाने की गुहार	20
पर्यावरण: प्राकृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन	22
राष्ट्रीय आपदा: स्वयंसेवक संघ का सेवाधर्म	24
वृक्ष: हमेशा पूजे जाते हैं हिंदू धर्म में	29
नक्षत्र: नवग्रह वाटिका	32
पर्यावरण संरक्षण: कुड़ी गांव का कमाल	34

EDITOR-IN-CHIEF
Rajesh K Rajan

CONSULTING EDITOR
Dr Atanu Mohapatra

EDITOR-ENVIRONMENT
Dr Dhiraj Kumar Singh

EDITOR ENGLISH
Dr Subhash Kumar

EDITOR HINDI
Ankur Vijaivargiya

EDITORIAL TEAM
Lokendra Singh
Dipti Sharma
Kavita Mishra

CREATIVE & GRAPHICS
Alekha S. Nayak

संपादकीय

Come September: साथ आएं और मुस्कुराएं

आप सब से *पर्यावरण Perspective* का अगस्त-सितंबर संयुक्त अंक साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। और ऐसे में बरबस याद आ जाती है Come September (1961), एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जो हमें मुस्कुराने नहीं, बल्कि ठहाका लगाने के लिए उकसाती है। शुरू में मैं एक अपराधबोध से ग्रस्त हो रहा था कि समय पर *पर्यावरण Perspective* का अगस्त संस्करण साझा नहीं कर पाया, पर जब अगस्त और सितंबर माह के घटनाक्रमों पर नजर डाली तो अपराधबोध धीरे-धीरे खुशी में बदलता गया। वजह भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, आजादी का अमृत महोत्सव या कहें कि हमारे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, 20 साल के संघर्ष के बाद अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से निकलना, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, इत्यादि। पर्यावरण हम सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि हम अपने इस संयुक्तांक में कोने-कोने से पर्यावरण से जुड़ी जमीनी कहानियां आपके लिए लाए हैं। पर पर्यावरण से हट कर, मैं आप सब को देश-दुनिया में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से भी रूबरू कराना चाहूंगा।

पूरा देश टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (जिसमें देश ने सात पदक: एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य हासिल किए) का जश्न मना रहा है। यकीनन देश के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन ने भारत की आकांक्षाओं को एक नई सुबह दी है। पर क्या हमारे आकार के देश को कई गुना ज्यादा पदक नहीं जीतने चाहिए? क्या हमें जमीनी स्तर पर अपने खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और एक नई खेल संस्कृति का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है? अब शायद ये समय आ गया है जब हम अपनी खेल की संस्कृति में आमूल परिवर्तन लायें। देश अपने आकार के हिसाब से पदक भी अपनी झोली में लाये और खेल की संस्कृति से जुड़ी तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए हम सब सरकार और तमाम हितधारकों पर दबाब बनायें, ताकि हमारा देश भी दुनिया के सबसे बड़े खेल ओलंपिक में अधिक गौरव प्राप्त कर सके।

आजादी का अमृत महोत्सव सरकार की ऐसी पहल है, जो भारतवासियों को 75 साल की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जायजा लेने और गौरवान्वित होने का अवसर दे रही है। इसी इरादे से प्रधानमंत्री ने 12 मार्च, 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। यह महोत्सव हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया है।

किसी भी राष्ट्र के लिए 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाना निश्चित ही एक पवित्र और खास अवसर होता है। हम भारतीय 15 अगस्त 1947 को इस दिन ही 74 साल पहले अंग्रेज़ों की जंजीर से मुक्त हुए थे और हमें आजादी मिली थी। इसे ही देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया और तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है। पहली पीढ़ी ने आजादी की लड़ाई खुद से लड़ी और बहुत कष्ट झेला। दूसरी पीढ़ी ने अपने बुजुर्गों और बाप-दादाओं से स्वतंत्रता की आपबीती कहानी सुनी और महसूस किया। अब वर्तमान में तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, जिसने न कुछ देखा, न सुना। यह आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मौजूदा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी असमानताओं को पीछे छोड़ते हुए एक खुशहाल भारत के निर्माण हेतु संकल्पित देशवासियों को ये महोत्सव प्रेरित करेगा। हमारी तीसरी पीढ़ी जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, देश को एक युवा राष्ट्र बनाती है। यही वो पीढ़ी है जो देश में अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखती है। गुणवत्ता वाली शिक्षा, ठीक सेहत और हर हाथ को हुनर मुहैया करा सकती है। अब अगर यह पीढ़ी देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बन गई, तो भारत को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने से कोई रोक नही सकता। इसलिए यही वह समय है जब हम अपने राष्ट्र के नए भविष्य वास्ते लक्ष्य निर्धारित करें।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन (5 सितंबर) को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब छात्रों ने डॉ. राधाकृष्णन से उनके जन्मदिन को एक विशेष रूप में मनाने की अनुमति मांगी, डॉ. राधाकृष्णन ने शिक्षकों के योगदान को समर्पित 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। तब से हर साल 5 सितंबर को तमाम शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

याद रहे 14 सिंतबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया। और तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पाठकों से एक ही आग्रह है कि *पर्यावरण Perspective* की नेक पहल को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने में हमारी मदद अवश्य करें, अपने क्षेत्रों में घटित प्रेरणादायी कहानियों को *surabhi.tomar@gmail.com* पर साझा करें और पर्यावरण से जुड़े हमारे प्रयासों को जानने के लिए *www.paryavaransanrakshan.org* पर जाना न भूलें।

(RAJESH K RAJAN)

Ecology

Restoring in a holistic way

By Ketaki Ghate and Manasi Karandikar

Why restoration ?

Most of the time, plantation of trees is the only preferred solution when it comes to nature conservation activities. Often monoculture of non-natives species is done wherein only one species is planted uniformly. These plantations do create greenery, and do have certain benefits but it does not create a forest as an ecosystem. So it is necessary and possible to go beyond this most popular solution and help nature in a holistic way. This brings us to the concept of "Restoration of nature". The results are beneficial to soil, water and biodiversity. We have been fortunate to witness this process on one of our projects in the village of Wan-Kuswade in Maharashtra which is a part of Sahyadri mountain range. Here is the story of this restoration effort.

The 24 acre piece of land that we have been working on since 2006, is owned by film actor Atul Kulkarni, actor Dhiresh Joshi and their families. They bought this land only to do nature conservation and to spend some time away from cities and enjoy nature's bounty. They approached oikos for ecological services for its execution. oikos is our ecological enterprise working for ecological restoration and biodiversity conservation since 2002. Having worked on more than 150 land parcels, we suggested the owners for conservation through restoration, which was agreed and work was started.

How?

As a first step, ecological assessment of the entire watershed of Wan-Kuswade village was done. The stream network, geology, forests and Sacred Groves (Devrai), biodiversity distribution within the catchment etc. was studied to understand the current natural set up of the surrounding area and its relation with the project land. Seasonal assessments were done to document the entire array of biodiversity thriving in the landscape. Looking at the climate and rainfall, this area should support semi-evergreen forests, but what you see within the watershed is fragmented patches of forests scattered within the vast open areas with grasses and shrubby clusters. The project land was part of such degraded open areas.

A detailed assessment of the project land was done to understand existing status of soil, habitats, and distribution of floral and faunal species. Part of the land is flat and Some have a gradual slope. The flat part hosted grasses with very few shrubs and a single tree of Anjani (Memecylon umbellatum) tree. On the slope, however, there were many shrubby clusters with sparsely standing trees. Inventories of habitats and species were done over a year. After completion of this baseline study, the direction and purpose of the work of restoration was decided. Objective was set to improve the texture and strength of the soil, to increase its moisture retention capacity, so that the biodiversity would increase and grow naturally.This process is also known as Assisted Natural Regeneration (ANR). Specific restoration techniques were designed for the same as follows.

1. Protection
2. Soil and Water conservation
3. Habitat creation
4. Seed dispersal
5. Plantation of native trees

Protection is extremely important in any restoration project to prevent and stop external pressures like

a) grazing by cattle, b) fire which is induced by locals deliberately, and c) cutting of trees by locals. This protection was assured by erecting a Dry Thorn fence all along boundaries. A live hedge was also created by planting local shrubs like Nirgudi (Vitex negundo), Karvi (Carvia

callosa) and selected trees (Ficus species). In addition, a fire line is done every year to prevent fires from entering the project land, wherein a belt of 10 ft width is burnt deliberately and carefully, so that continuity is cut. For soil and water conservation, various physical structures were constructed like stone lines, stone bunds, ponds etc. These were done using locally available stones. Use of cement or any external materials was completely avoided to keep the carbon and ecological footprint of the project to the minimum. Specific erosional features were identified and repaired as per the

need. In certain places, habitats were created by arranging stones in a specific manner, piling up leaves and by planting host plants and food plants for birds and butterflies. Local grasses were given special importance by offering complete protection to them. Plantation of suitable native plants is being done every year, though the aim of the project is not plantation or quick afforestation. Native plants are selected carefully as per the site specific soil and moisture conditions. Initially hardy species were planted and then more common and then rare, endemic species were added. Seed dispersal is also done every year at suitable places.

Results

As a result of all these techniques, various positive changes were observed in all these years.

• The biomass on the ground started increasing and continues to increase every year. This has changed the physical structure of land. This biomass is serving as a natural insulating layer over the soil which has improved its temperature, moisture, fertility, germination capacity and biodiversity.

• Seeds of many native plants have started germinating naturally. At the same time, the number and size of shrubs has increased because of the ban on cutting. As a result, the vegetation cover on the ground has increased significantly. So also the 'diversity'!

• A beautiful mosaic of habitats with grassy patches, shrub clusters, and perennial vegetation can be seen today on the land which had been dry and open for years.

• Flowering and fruiting of diverse native plants provide food and shelter for many micro-organisms. We look at species and their activity as an 'indicator'. Birds have started to nest and breed indicating creation of safe sites and enough food for them. Increased numbers of lizards are indicating a higher insect population. Flora and micro fauna is the base of the food chain. Appearance of birds of prey also indicates the establishment of a complete food chain. Occurrence of rare animals such as Sicilians, Leeches using the land indicates restoration of specific habitats for them which were completely absent in initial years.

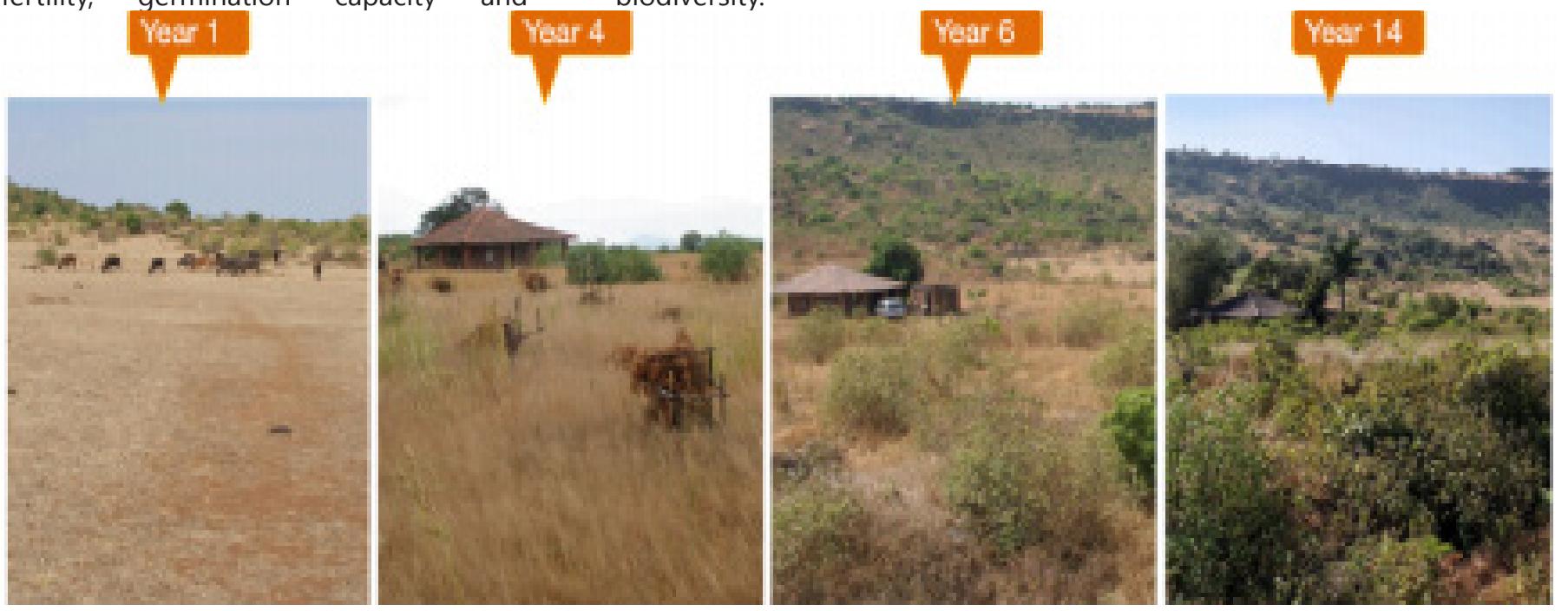

• Soil erosion is reduced as soil is arrested behind the stone bunds and stone lines. By preventing erosion on a large scale, rainwater seepage has increased. Soil texture has improved as a lot of organic matter started going into topsoil which was food for earthworms and in turn they created a lot of aeration in the soil, making way for other invertebrates.

• Another striking difference was observed in better soil temperatures. Initially the open soil would get heated up to 56 °C. But with a layer of grass biomass, it has lowered down to 40 °C. The land, which used to get dry quickly after the rains, now retains moisture for a long time, till April-May. This is most important for many microbes which now thrive even after the monsoon. Also, the land which was earlier covered only with 'seasonal grasses', now has a layer of 'perennial grasses and shrubbery.' Saplings need no watering till March - April. In earlier years, we would start watering the saplings immediately after monsoon. But now saplings survive on soil moisture till summer.

Conclusion

From all these observations, it can be said that the diversity of natural habitats on this land patch has improved. Interestingly, the neighbouring patch of the land is still at the same stage the way it was 15 years back, and the contrast in comparison is striking. This project has climbed up two stages on the ladder of ecological succession, a process of going towards maturity of the ecosystem, and the correct path of forest formation. While it is difficult to say how long it will take to reach the goal, a wait of twenty to fifty years seems natural. As the owner of land, Atul Kulkarni says, "... all this is for nature and for our future generations. Let's try and give back to nature and enjoy this process !"

The processes of restoration involve patience and faith, but they teach us more about Nature herself as we witness her magical ability to regenerate!

Ecosystem

Prevent, Halt and Restore

By Dr Avilash Roul

Ecosystem Restoration is the theme of this World Environment Day which is being celebrated across the word on 5th June. While Pakistan is the global host of this year's world environment day, the United Nation has launched the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030. The dedicated UN decade would likely to bring the focus of world governments in preventing, halting and reversing the degradation of ecosphere in their respective sovereign control as well as beyond. Since 1972 United Nation sponsored Conference of Human Environment (UNCHE) at Stockholm, international community- governments, non-government organisations, citizens, youth and children have been celebrating June 5th as World Environment Day.

Through the civilizational progress, it's the anthropocentrism which has either directly or indirectly and knowingly or unknowingly diminished the value and sense of ecocentrism- a vital component of survival of humankind. The Pandemic of the century that has already caused loss of million lives is an effect of large scale unstoppable ecosystem degradation. As humankind continue unabated to encroach on fragile ecosystems, emergence of zoonotic diseases will threaten lives of millions. The modern humankind considers services provided by ecosystems only in terms of limited and narrow economic cost. The result is overexploitation of nature and natural resources. Human activity has altered almost 75 per cent of the earth's surface, cornering wildlife and nature to a smaller area of the planet. Almost 1 million flora and fauna species are threatened with extinction. Land degradation has reduced the productivity of 23% of the global land surface. Nearly 100-300 million people are at increased risk of floods and cyclones due to loss of coastal habitats and protection. The Global Assessment Report of Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) alerts to the world that nature's dangerous decline 'unprecedented'; species extinction rates 'accelerating' than never before.

Ecosystems support all life on Earth as web of life. The UN sponsored Millennium Ecosystem Assessment (MA) identified four major categories of ecosystem services: provisioning (food, fresh water, fuel, fiber, and other goods), regulating (climate, water,

disease regulation as well as pollination), cultural (educational, aesthetic, and cultural heritage values as well as recreation and tourism) and supporting services (soil formation and nutrient cycling). Therefore, the Earth needs urgent healing. Ten more years are now with humankind to restore, or at least to minimise the pace of degradation of the planet.

The healthier the ecosystems are, the healthier the planet - and its people. According to 'State of Finance for Nature' Report (2021), authored by UN Environment Program, World Economic Forum and Economic and Land Degradation Initiative, the World needs 8.1 trillion USD investment in nature by 2050 to tackle multiple but interlinked planetary crisis of ending poverty, combating climate change, preventing mass extinction and land degradation.

All kinds of ecosystems- farmlands, forests, lakes and rivers, grasslands and savannahs, mountains, oceans and coasts, wetlands, and cities- require sustenance by each and every one from governments and development agencies to businesses, communities and individuals. The UN estimates that by 2030, the restoration of 350 million hectares of degraded terrestrial and aquatic ecosystems could generate 9 trillion USD in ecosystem services. Restoration could also remove 13 to 26 gigatons of greenhouse gases (GHG) - gases causing climate change - from the atmosphere, which would complement efforts under Paris Agreement on Climate Change. The economic benefits of such interventions in ecosystem restoration is nine times greater instead of inaction or business as usual practices. While restoration of a small ecosystem can protect and improve the livelihoods of people depending on that, the large restoration can provide security of states and nations. It helps to regulate disease and reduce the risk of natural disasters. In fact, restoration of ecosystems can help achieve all of the Sustainable Development Goals (SDGs) as most of its 17 Goals are interlinked.

Restoring Marine Ecosystems

Marine ecosystems are under direct attack from pollution, climate change and overexploitation. The oceans play an important role in supporting life on earth while covering more than 70 per cent of the surface of the planet. Having most diverse and important ecosystem, oceans contribute to global and regional elemental cycling, and regulating the climate. The ocean provides natural resources including food, materials, substances, and energy. Marine resources are particularly important for 40 percent of world population living in coastal communities. Meanwhile, oceans help regulate the global ecosystem by absorbing heat and carbon dioxide (CO2) from the atmosphere

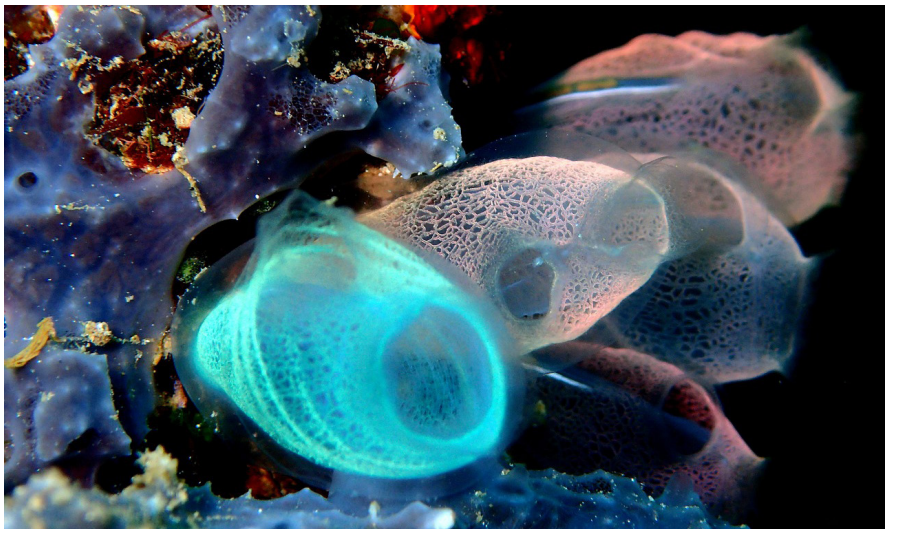

However, oceans and coastal areas are extremely vulnerable to environmental degradation, overfishing, climate change and pollution. In 2015, 33% of marine fish stocks were being harvested at unsustainable levels and 60% were maximally sustainably fished. Plastic pollution has increased tenfold since 1980, 300-400 million tons of heavy metals, solvents, toxic sludge and other wastes from industrial facilities are dumped annually into the world's waters, and fertilizers entering coastal ecosystems have produced more than 400 ocean 'dead zones'. Also, under the present ocean (non)governance, free for one country in sovereign water and Exclusive Economic Zone (EEZ) to free for all beyond EEZs, both notions have depleted the Ocean by competing demands with increasing disputes among countries.

The Indian Ocean, according to the Indian Ocean Experiment (INDOEX), has been gravely polluted by plastic debris and chemical runoff. It has documented widespread pollution covering about 10 million square kilometre (3.86 million square miles). According to World Wide Fund for Nature (WWF), more than 80% of marine pollution is caused by land-based activities that cause oil spills, fertilizers and toxic chemical runoff and the discharge of untreated sewage. Additionally, it bears the brunt of oil transits thereby further risking oil spills and dangers due to heavy traffic.

Last month (May 20) fire incident of Singapore-registered ship MV X-Press Pearl, carrying chemicals and plastic, and subsequent explosion, have registered serious ecological hazards due to oil spill and spreading of tiny plastic pearls along the Sri Lankan coast by threatening fragile marine ecosystem. The ship which was carrying 350 tonnes of oil in its fuel tank will be disastrous to the costal ecosystem despite Island country's Marine Environment Protection Authority (MEPA) would able to handle that. This incident is not less than the Tory Canyon oil spill in UK coast in 1966-67, which was a major ecological disaster. The MV X-Press Pearl case must ignite the environmental consciousness not only in Sri Lanka but in South Asia.

To avoid such high risk incidents and to protect, conserve and manage ocean ecosystems in sustainable manner, the littoral countries must come together at the earliest to forge a long-term agreement. The ongoing negotiation to produce a legally binding instrument for the conservation and sustainable use of 'Marine Biodiversity beyond National Jurisdiction' (MBBNJ) under the UN Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) is a step in right direction. The SDG -14 calls upon the governments to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. On a regional scale, it is imperative for India to take the stewardship in ocean conservation with other littoral countries. The UN Ecosystem Restoration Decade has provided the opportunity to India and other littoral countries to begin a dialogue for a long-term agreement at least on the eastern side as a proposed Bay of Bengal Initiative on Restoring Marine Ecosystems (BBIRME).

The slogan for this world environment day is 'reimagine, recreate and restore' ecosystems for healing the planet. To add and furthering the objectives in spirit and letter, the slogan shall be with co-reimagine, co-recreate and co-restore by emphasising the informed participation of communities, citizens and stakeholders who are depending on the specific ecosystems for their livelihood as priority.

(The Author is Guest Professor/ Principal Scientist at IIT Madras, Chennai)

Masks

Saving Humans, Overburdening Ecosystem

By Sarika Anuradha

Mask use has become mandatory to prevent the transmission of COVID-19. The increasing usage, however, is gravely affecting the ecosystem. In Frontiers of Environmental Science & Engineering journal, researchers warn that "With increasing reports on inappropriate disposal of masks, it is urgent to recognize this potential environmental threat and prevent it from becoming the next plastic problem".

With the ongoing spike of virus attacks and our war-like response to limit the expansion of the virus, this year has been jam-packed with activity. The vaccination campaign is in full-swing and scientists are racing against time to find a way to control the virus. Nonetheless, this pandemic serves as a reminder that unchecked manipulation of natural dynamics inevitably backfires on humanity. Unless we change our business as usual approach to environmental resources, our susceptibility towards yet-unknown pathogens will skyrocket. The practice of sustainability has never felt more vital to our species' survival. A year ago, disposable face masks, gloves and wipes were not so much of a necessity. Researchers have cautioned that disposable face masks could be spewing chemical contaminants and nano-plastics into the environment. Scientists around the globe are emphasizing for conducting more research in this field, for understanding the exact impact of mask disposal on the environment. Facial masks, gloves, and wipes are not recyclable in most municipal systems and should not be placed in any domestic recycling container. Masks may contain a compound of paper and polymers that cannot be divided into pure streaming of individual recycling materials, including polypropylene and polyester. They are smaller in size and are caught in recycling machinery that causes failures. The need of the hour is to secure the life of other people in the present scenario of the COVID-19 crisis. Precautionary measures are important in this pandemic period, but consequent environment deterioration must also be evaluated. Massive amount of waste is generated by disposable face masks. Apart from critical clinical settings, many reusable and eco-friendly solutions can be opted by people. Around 129 billion face masks are used per month, which is approximately three million masks per minute. They are mostly disposable facial masks made of plastic microfibers, which are not easily biodegradable, but can split up into smaller, ecological microplastic and nanoplastic particles. However, since no separate guidelines are prepared for the disposal of masks, scientists and others are disposing them as a solid waste as per the guidelines.

Fig 1: Showing harsh reality of new emerging waste, amidst of Covid-19 pandemic

The unsystematic way of disposing discarded masks by people has resulted in a surge of unprecedented increase in single used personal protective veil. This releases a significant amount of particulate matter into the atmosphere, which can wind up in the streets and dumping sites. It also reaches the aquatic bodies, reservoirs, as well as fresh and salt water. Furthermore, the manufacture of face masks leads to CO2 emissions, which contributes to global warming. Propylene, small aluminum strips, and polypropylene, which are used in the manufacture of N95 and surgical masks, emit a significant amount of CO2. Also, the production of fabric, as well as the stitching and weaving processes used in the creation of cloth masks, contributes to CO2 emissions in the environment.

Hospital face masks and other mixed garbage are collected and transferred to an incinerator and landfill. However, such approaches often have negative environmental consequences due to the presence of plastics in the masks. Generally, plastics are chemically stable, resistant to corrosion and hard to degrade by microbes. Hence, they prefer to stay in the soil profile, posing harm to the soil ecosystem by impacting microbial community. Public worries regarding emissions of GHGs through waste are crucial but most problematic issues in dumping includes transportation of waste that shares high energy. This also leads to release in harmful pollutants such as dioxins and furans. Apart from this, locally dumping mask on the street or roadsides are also affecting the avian and animal ecosystem. For example, in Columbia, a bird was tangled in a discarded face mask leading to congestion after its body and beak were wrapped in the mask. Furthermore, if the plastic enters into stomach, it restricts food intake and lead animals to suffer and die if they mistook the mask for food, which happens all too often. Marine sediments adsorb

micro contaminants and toxins released during long-term gradual decay of masks and gloves products that make sure the pollutant particles bind to the surface as a toxic film. Consequently, the marine animals that indirectly consume plastic particles are weakened, also making them directly vulnerable to other threats. The various abiotic processes, such as photo degradation, weathering, corrosion and aquatic immersion etc., can cause the macro plastic fragmentation, resulting in subsequent microplastics release from mask waste. As a result, bioaccumulation of microplastics occurs in the primary food web that sustains biosphere survival, culminating in ecosystem deterioration by effecting food chain cascade. This has not just negative environmental consequences, but also has negative economic and societal consequences.

Table: 1 Showing occurrence of CO2- eq. GHGs emission per single mask during different type of mask manufacture (Source- Selvaranjan.et. al., 2021)

Mask Type	CO_2 – eq. GHGs per single mask manufacture
N 95	50 G
Surgical	59 G
Cloth	60G

Taking this issue into consideration, the precautions to minimize the negative effects of wearing a face mask includes switching to biodegradable & reusable options like organic biodegradable mask which are made of linen, cotton, silk, bamboo and hemp etc. If something goes wrong with the one you're using, immediately dispose of it in a bin with a cover. If this isn't possible, dispose it properly in a public bin. Various technology such as mechanical recycling, chemical recycling, incineration and pyrolysis etc., could allow plastic particles to be separated from mask waste. The separated plastic derivatives can be used as substitute for the cement and aggregates partly in building materials. It is robust, long-lasting, water-resistant, easy to mottle and recycle. It can thus be used in the building sectors (Selvaranjan et.al., 2021). It can be used for isolating building wraps, industrial tapes, plastic items such as pipes and bricks from masonry. Because it is an immersing waste, limited research is available. So, more efficiently and cost-effective research is needed to find alternative of reusing and disposing the particular waste. It also promotes a cultural shift to recycling and reuse, which is essential in order to decrease the demand for disposable face masks and harmonize it with wider management of wastes and attitudes to climate change.

Stepwell

The Maha Story

By Rohan Kale

One of the areas of knowledge India excelled in the past was building efficient water management systems. The historical water conservation and supply systems in the arid regions of India are testimony to this fact. However, thanks to the changed notion of development, many of the structures that served the need of people for centuries suddenly became redundant and are lying in the state of misery today. At a time when several parts of the country are facing severe water shortage, the need to revive these invaluable water sources cannot be emphasised more.

Stepwell is undoubtably one such system that was built for water conservation. It can be reached through descending series of steps. They are constructed in different architectural designs and serve the water requirement of people for drinking, bathing, washing and even irrigation. The State of Maharashtra has thousands of Stepwells. If revived, they could become an excellent source of water for drinking and domestic use for people in rural areas. And the first step to do this is to map and document all the stepwells in the state.

Trigger Point for starting this campaign

During exploration of stepwells in Maharashtra, we found numerous stepwells in very neglected state. Many people in our Maharashtra state are actually not aware that there are magnificent stepwells across Maharashtra. Those few who were aware of stepwells were just exploring them and were writing blogs on Facebook. However, this was not solving the purpose as stepwells continued to be in sad state. Hence, to generate awareness about stepwells and with a strong determination to map, document and revive thousands of stepwells, I along with my friend initiated this Maharashtra Stepwells Campaign.

My Journey

For setting up this campaign, I solo-travelled on my bike approximately 14,000 kms across Maharashtra (Konkan, Paschim Maharashtra, Marathwada, Vidarbha, Nashik) and personally explored more than 400 Stepwells and approached/ met Heritage Explorers, Historians, Indologist, Researchers, Regional Archaeology Teams and explained them about this campaign to work as one team and received active support and participation from all of them. It is because of the support from all these people that we are able to set up a huge platform for this campaign to run successfully.

With active participation of people across Maharashtra, we have mapped more than 1200 Stepwells so far. Details of these are available on our website: www.indianstepwells.com (Sub Section : Maharashtra Stepwells).

Vision

~ Heritage Conservation

~ Reviving Stepwells

~ Tourism Development

~ Study of Ancient Trade Routes (as stepwells were built along trade routes).

~ Celebrate Maharashtra Stepwell Festival by lighting up 150-200 Stepwells at a time next year.

Goals

~ Creating the largest and most reliable database of stepwells of Maharashtra for research and conservation purposes.

~ Identify thousands of Stepwells (capturing gps coordinates and mapping them on custom google map for public view).

~ Creating Manuals for identifying different classifications of step-wells (regional rerms are Barav/Bawdi/Ghodbav), step-tanks, kund, pushkarni, pokhran, helical stepwells, rock-cut stepwells.

~ Standardized Written Documentation Format across Maharashtra.

~ Architectural Documentation (tie up with regionwise architectural colleges / professional architects).

~ Photographic Documentation including drone shots.

~ Heritage Documentation (Indologist + Historians clubbed).

~ Collaborate with NGO's for cleanliness drives and for reviving of stepwells / ecological water purification of stepwells.

~ Collaborating with People and Government for conservation of stepwells.

~ Encourage villagers to also develop unique stepwells as tourist attractions.

~ Sharing good work done by respective village locals/ authorities in conserving stepwells through social and print media to motivate people of other villages.

~ Organize free study tours for students.

~ Make all the documented data available online in just one click for public view.

As per our analysis there must be approx 20,000-25,000 thousand step-wells, step-tanks, kund, pushkarni across Maharashtra and if we take sincere efforts we will be able to locate minimum of 5000 stepwells in the first phase (vision of 5 years).

Link to view locations of 1200+ stepwells in Maharashtra: https://tinyurl.com/54sut3wv

~ Zoom in and click on any of the Pin Locations (Blue-White Circle).

~ It will reflect the Stepwell Location and Photo of the stepwell if uploaded.

~ Click on the Direction Button and it route you to the stepwell location.

~ This custom google map will automatically get stored in your google maps and every time we add new stepwells, it will get auto updated in your respective google maps.

Work in progress

~ Identifying Taluka Coordinators who can do village to village mapping of their respective talukas.

~ Also identifying people across all villages in Maharashtra to ease and fast-track the mapping of stepwells.

~ Mapping approximately 4-5 stepwells daily by coordinating with our mapping team (Mapping & Tracking the Progress of this Project).

~ Spreading a word about this campaign by giving presentations in different colleges and generating awareness.

~ Creating database of people working in different sections like Architects, Indologist, Historians, Geologist, Photographers.

~ In discussion with State Archaeology Team / State Gazetteer Team to understand their documentation parameters and seeking their guidance to create manuals, processes and frameworks under which every section team of this campaign will operate. This project would require close coordination and a strong collaboration with state archaeology team.

~ In discussion with different NGO's in Pune / Aurangabad Region for working out plan of action for reviving the stepwells especially in the regions of Marathwada/Vidarbha where there is scarcity of water / drought regions.
~ Developing tourism/promotion of stepwells in discussion with the Maharashtra State Tourism and seeking their active support for promotion of Maharashtra Stepwell Festival to be celebrated next year.
~ Managing different platforms required for this campaign (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Website) for creating continuous awareness and generating interest amongst youth towards stepwells.
~ At present, we have consent of approximately 150 villagers across Maharashtra for celebrating stepwell festival next year on day of Maha Shivratri (final call will be taken a month before by gauging the pandemic situation at that time).
~ Trying to unite all the people in our state as *One_Team_ Maharashtra* and assign them section wise responsibilities to make this the biggest stepwell campaign in state of Maharashtra. Let's join hands to revive and conserve our invaluable heritage sites - The Stepwells of Maharashtra.

(Inauguration of city forest on 5 June 2020 by Minister of MOEFCC, Source: PIB)

Urban Forest

Vulnerabilities and Resilience

Climate change has worsened the Indian cities and made them more vulnerable

By Dr Avilash Roul

Climate change exacerbates the risks of vulnerabilities of many cities in the world especially cities of India. Accelerated urbanization in Indian cities and its surrounding areas peri-urban(an area immediately adjacent to a city or urban area),has already put pressure on land use especially on green vegetation and forests. Cities are subjected to multiple climate hazards depending upon their geographical location and climatic conditions, ranging from increased and frequent flooding and water logging, landslides to heat waves, sea-level rise, cyclone and storm surges. While cities are exceptionally expanding under both internal and external stimuli affecting vegetation cover, disastrous weather events have aggravated issues of liveability in most cities. Instead, urban and peri-urban forest would help achieve food security, provide livelihood, alleviate poverty, reduce risks of natural disaster, address climate change impacts and create recreational, cultural and social opportunities.

Vulnerable Cities

The overarching feature of the landscape of many cities and towns in India is that they have taken their present forms and shapes by directly altering their natural surroundings especially green vegetation. Emerging urban spaces in cities are not bereft of such transforming effect on natural surroundings especially forest and green cover by clearing the natural growth forest and failing trees

without understanding the services provided by the forest and tree cover. From heat wave and waterlogging in Bhubaneswar, the capital of Odisha to flood and cyclone in Chennai, coastal capital of Tamil Nadu, these dynamically growing urban environments are failing in adapting/or managing human interaction and climate change risks. These two cities emerge with unique similarities of its heritage importance as 'Temple Cities' including natural growth forests and tree covers in and around city boundaries as well as primary engines of economic growth. Similarly, these cities are carrying the British Colonial legacy of governing and administering the forest resources.

After the 2015 floods and 2016 Cyclone Vardah, the ever-growing capital city Chennai has arguably been more exposed in its vulnerability than before on the face of climatic variability (Roul, 2018). Meanwhile, rapid urbanisation in Bhubaneswar and its extension has resulted in 89 % decrease in dense vegetation, about 2% decrease in water bodies in the last 15 years. Since 1999 when a Super Cyclone uprooted many trees in the city, remaining trees have been cut for infrastructure expansion. Cyclone Fani in 2019 had added the destruction of remaining green cover in the city. Loss of vegetation, destruction of water bodies and increase in paved area negatively impacts thermal and radiative properties of surface, making cities hotter than surrounding non-urban areas. Even Bhubaneswar, which is only a tier-2 city, is witnessing an increase in temperature due to changes in land surface leading to urban heat island effect.

Importance of Urban and peri-urban forest

Forest or 'van' has been the lungs of all living beings in the ecosphere. Forest and tree cover are critical components of urban and peri-urban environment, which moderate microclimate, enable ground water recharge, provide shade and conserve local biodiversity, improve quality of life for city dwellers by providing recreational avenues including public space for better social cohesion, significant health benefits, aesthetics as well as mitigating climate change. Urban and peri-urban forest, considers to be the life line of cities, has also affected by the climate change.

However, urban forest is not new to India. It has many names and forms. In the Ramayana, mention is made of the Ashok Van, in which Sita was held captive. The planting of roadside avenue trees (margeshuvriksha) was an important contribution of King Ashoka. In old Sanskrit and Buddhist literature there are many references to the urban forests or urban tree plantation. Ancient India had numerous examples of cities creating, adoring and maintaining various forms of gardens, orchards and forests. Arthashastra tells us that forests for recreation and for economic benefits were grown adjoining to the countryside (Deshkar, 2010). In ancient India, parks, groves and gardens were laid out for the entertainment of the citizens in every city (Singh, 1976). Public gardens (nagara opavana) were generally situated outside the town and were provided by the government for health, recreation and enjoyment of the citizens. The radiating centre of ancient culture, present day Madurai city, was decorated in swath of Kadamba trees (Neolamarckia cadamba). Several descriptions of the splendour of ancient temple cities in India with vast forest and tree covers were known and celebrated. Commonly, a Défense was created by trees and shrubs planted so as to form a forest.

In post-Independent India, Chandigarh the planned city has taken special care by including urban forestry in the city planning. Recently, numerous examples of emerging forms and types of urban and peri-urban forests are being witnessed in and around Indian cities. On 7 September 2020, Telugu movie actor Prabhas adopted 1,650 acres of Khazipally Reserve Forest near Dundigal, in the outskirts of Hyderabad for developing into a conservation zone and an Urban Forest Park.

Urban and peri-urban Forest in Context

There is no uniform definition of urban forests. There lies the discontentment in formulating a uniform policy or guidelines in India so far. In 2014, an attempt was made to prepare a

(Reserve Forest in Chennai city)

draft policy of urban forest. However, Food and Agriculture Organisation (FAO) aims to indicate that urban and peri-urban forest as networks or systems comprising all woodlands, groups of trees, and individual trees located in urban and peri-urban areas (FAO, 2009). Urban forests are the backbone of the green infrastructure, bridging rural and urban areas and amending a city's environmental footprint. Further, from an administrative point of view, Urban Forest can be looked at as an integrated, interdisciplinary, participatory and strategic approach to planning and managing tree resources in urban and peri-urban areas for their economic, environmental and sociocultural benefits. Parks, city forests, biodiversity parks and other green belts and so on contribute to Urban and peri-urban forestry.

While contemporary urban and peri-urban forest has its origin in cities in western countries (Konijnendijk, 2006), it has been gradually emerging in India as a focused discussion among urban planners in last decade or so. There is no dearth of literature on international scale related to urban forest. There are two distinct group of literature focusing on urban forestry in North American cities and European cities. Urban green cover provides multiple benefits to city residents (Dearborn and Kark, 2009), including the mitigation of urban heat island effects, reduction of air and noise pollution, and protection against foolding (The Nature Conservancy, 2016). Food trees in urban public spaces can provide economic and food security benefits (Lafontaine-Messier et al., 2016). The environmental services as benefits of urban forest are long been established in international literature.

Most of the existing literature related to urban forest in India follows the prescriptions of international practices. The ambiguity of defining urban forests in Indian context has its own challenges and constraints owing to contested domain of forest as a whole. Notwithstanding the definitional ambiguity, most literature consider green spaces, trees and tree cover, parks etc within cities as urban forests by deliberately keeping recorded forests in and around cities at bay. Most of the literature prescribe allocation of green spaces in Jaipur (Singh 2010), greening Delhi by legally managing trees as a model framework for other cities (Sinha 2013), recreational benefit of parks and trees in Chandigarh (Chaudhary 2013) and management of parks in Indian cities (Chaudhary 2010), understanding biodiversity in sacred places of Bengaluru (Nagendra et. al., 2018) and so on. With focus on urban spaces, literature limits the scope of discourse in managing trees and parks in cities rather than opening up a larger discussion on urban forest equity.

Recent Development in Urban Forest in India

'Nagar Van' (city forest) scheme initiated by the central government is one of the very important initiative in right direction. Despite its announcement in 2015, the scheme has not seen its potential yet. The Ministry of Environment and Forest and Climate Change, here after Ministry, has launched Nagar Vana Udyan Yojana to create city forest in class-1 cities having municipality. Under this scheme a minimum of 20 hectares of forests will be created in the city. These city forests will provide the city dwellers a wholesome natural environment for recreation and will contribute to improvement of the city's environment by pollution mitigation, cleaner air, noise reduction, water harvesting and reduction of heat island effect. City authorities are encouraged to have a city forest comprising area up to 100 ha in forest area within their jurisdiction for deriving maximum ecological and environmental benefits. This is also linked to the Schools Nursery Yojana that aims to build lasting bond between students and nature. An amount of Rs. 1.54 crore (for 505 school nurseries) and Rs. 51.24 crore (for 46 Nagar Van Udyans) respectively have been released under these schemes till February 2020 (GoI, 2020). While urban forestry is a permissible activity under the provisions of Compensatory Fund Act, 2016, according to Ministry, under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), 1437 No. of parks over 2628 acres of land have been developed in the cities. In addition, several urban local bodies (ULBs) have undertaken various plantation activities under Jal Shakti Abhiyan (JSA) for water conservation.

(Chandaka Reserve Forest in Bhubaneswar Municipality)

However, on the environment day this year, Minister Shri Prakash Javadekar had announced to accelerate establishing 200 Nagar Van (city forest) within five years on any forest land inside a city or any other vacant land (PIB, 2020). The Nagar Van Udyan Yojana aims at developing 200 Nagar Van (City Forests) across the country in cities having Municipal Corporation or Municipalities by involving local communities, educational institutions, local bodies, NGOs etc (PIB, 2020a). Van Udyan once established will be maintained by the State Government according to the Ministry. Implementation of the 'Nagar Van' scheme to develop the urban forests in India will be in collaborative fashion by involving local communities, industries, local bodies, NGOs etc. It may take shape of public private partnership (PPP) mode or a collaborative approach as the central government aims at. In August, the Ministry has selected Itanagar for implementation of the 'Nagar Van' scheme. While the details are to be explored and thrashed out on various items especially on specific lands to be allotted or diverted for urban forestry, the initiative is timely and much needed.

Advancing Urban Forest Agenda

Under the urban development framework, cities, like Chennai and Bhubaneswar, are being re-oriented towards SMART city and Resilient City by respective state and national governments. Despite having large swath of natural growth forests and tree cover in their urban and peri-urban limits, the city planning documents are not comprehensively considering the role and function of green cover to the cities' sustainability. The planning merely considers, if any, the resilience of physical structures rather than the socio-ecological resilience in the city. Consequently, urban and peri-urban forest as an emerging concept in India have been facing the challenge of conflicting and overlapping governance domain.

While understanding urban and peri-urban forestry in India is in its embryonic stage, further research must be attempted to understand the challenges and constraints of urban and peri-urban forest governance in cities. If urban agendas in India would be considering comprehensively the aspect of citizens' urban forest? What if the discourse on urban forestry would like to bring recorded forest in cities as many cities' administrative boundaries is overlapping with recorded forest lands like in Chennai and Bhubaneswar.

However, areas for the development of urban forest shall not be wrangled in local politics or contested domain by the shutting the access to general public to such open spaces. In India, with the increasing rate of urbanization and demand for utilization of natural resources coupled with severe risk of climate change, the role and responsibility of governance units becomes critical. Local urban authorities are struggling to strike the balance between protecting the environment from degradation and reaping the maximum economic benefits from the emergence of rapid urbanization as well adapting to the vagaries of climate change.

Integration of urban and peri-urban forest into city planning remains a critical component that needs to be advanced. With the 'Nagar Van' scheme, it's logically prudent that local urban authorities will be implementing the urban forest agenda in inclusive manner. For various initiatives taken up by national government to make sustainable habitats including SMART city, Resilient city, Urban Habitat, R-Urban, it is important to bring the focus on integration and mainstreaming of urban and peri-urban forests into city planning documents, city disaster plans and city action plans on climate change. Under the SDGs targets especially Goal-13 and UN sponsored Urban Agenda, citizens' urban forests, which envisage a symbiotic relationship between human and nature, shall be aimed at in India. Understanding and awareness of co-benefits from urban forest among the society must be shared and accelerated. The participation and contribution of citizens' in increasing green vegetation around their settlements will add up to the national target of Green India Mission. Knowing that not one size fits for all, last but not the least, a national policy or guidelines on urban and peri-urban forest is long overdue.

References

Brandta, Leslie, et.al.,(2016), "A Framework for Adapting urban forest to climate change", Environmental Science & Policy, 66, pp. 393-404

Chaudhary, Pradeep (2013), "Valuing recreational benefits of urban forestry-A case study of Chandigarh city of India", International Journal of Environmental Science, 3 (5), pp. 1785-1789

Chaudhary, P. and V. P. Tewari (2010), Managing urban parks and garden in developing countries, a case from an Indian cities, International Journal of Environment and Sustainable Development (i): 30-36

Deshkar, Sameer M, (2010), "Kautilya Arthashastra and its relevance to Urban Planning Studies", Journal of Institute of Town Planners, 7 (1), pp. 87-95

FAO (2009), FAO Collaborative Meeting on Urban and Peri-urban Forestry: Trees Connecting People, Working Paper-2, Rome: FAO

Knuth, Lidija (2005), Legal and Institutional Aspects of Urban and peri-urban Forestry and Greening, Rome: FAO

Konijnendijk, Cecil C, et al., (2006), "Defining urban forestry—a comparative perspective of North America and Europe", Urban Forestry and Urban Greening, 4, pp. 93-103.

Lafontaine-Messier, et al, (2016), Profitability of food trees planted in urban public green areas, Urban Forestry and Urban Greening, 16, pp.197–207.

MOEF (2014), Draft Guidelines for Conservation, Development and Management of Urban Greens, New Delhi: MOEF (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India).

Salbitano, Fabio (2014), "Urban and peri-urban forestry as a valuable strategy towards African urban sustainable development" Nature and Fauna, 28 (2), pp. 21-26

Singh, H S (2013), "Tree density and canopy cover in the urban areas in Gujarat, India", Current Science, 104 (10), 1294-1299

Singh, Ram Bachan (1976), "Cities and Parks in Ancient India", Ekistics, 42 (253), pp. 372-376

Sinha, Rama Shankar (2013), "Urban Forestry: Urbanisation and Greening of Indian Cities- Efforts for Green Delhi", [Online Web] URL: http://www.teriuniversity.ac.in/mct/pdf/assignment/Rama-Shankar-Sinha.pdf, Accessed on 26 September 2016

Singh, Vijai Shanker, ET. al., (2010), Urban Forests and Open Green Spaces: Lessons for Jaipur City, Occasional Paper, Rajasthan State Pollution Control Board, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/RSPCB-OP-1-2010.pdf

Nagendra, Harini et al., (2018), "Biodiversity in sacred urban spaces of Bengaluru, India", Urban Forestry & Urban Greening, 32 (2018) 64–70

Dearborn, D.C. and Kark, S. (2009), "Motivations for conserving urban biodiversity", Conservation Biology, 24 (2), 432–440.

The Nature Conservancy (2016), Planting healthy air: a global analysis of the role of urban trees in addressing particulate matter pollution and extreme heat. Nature Conservancy: Washington DC.

Roul, Avilash (2018), "Is Chennai Climate Proof" in State of India's Environment, CSE: New Delhi.

Press Information Bureau (PIB) (2020), 'Urban Forest scheme to develop 200 'Nagar Van' across the country in next five years', https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629563

PIB (2020a), Urban Forest through People's Participation, http://pibcms.nic.in/WriteReadData/userfiles/Final%20urban%20forestry%20booklet%203-6-2020.pdf

GoI (2020), Social Forestry Schemes, Starred Question No: 85, Lok Sabha, 07 February 2020.

(The Author is Guest Professor/ Principal Scientist at IIT Madras, Chennai)

Astrology

The Celestial Sphere

By Pradhuman Suri

Astrology believes that whatever things are being created on this earth, it is being created due to the influence of some planet or constellation. The Moon and the Sun influence our earth the most. Then Jupiter, Mars and Venus. After this, the environment of the earth from the planets like Saturn etc.

Importance of astrology in human life?

The word 'Jyotish' means having light. Jyoti means light, without which life is incomplete. The eye can see the scene only in the presence of light, not in the dark. In this sense, astrology is the science that illuminates the unattainable - the invisible. Since time immemorial, man has been hankering to attain or to know about the unattainable. The option of reimbursement of this desire was created in the form of astrology, in which undertaking is done to predict future events. Astrology is basically a statistical science based on time calculations, in which the more accurate the calculations, the more likely they are to be true.

The importance of trees in our religion is that the virtue which is unattainable by performing many yagyas or digging a pond or even by worshiping God, that virtue is easily attained by planting just one sapling. This gives life to many living beings. In astrology and Vastu Shastra, the relation of trees with man has been depicted.

.

Why the need for astrology?

Man has been constantly trying to satisfy his curiosity and thirst. Continuing efforts have been made to solve the problems of creation, this effort has been given the name of science today. In the same way, what can a man do next in his life? Why is it happening in life? Curious to know the answers to these questions. The answers to these questions can be obtained through astrology. The planetary system located in the human body is directly related to the outer solar system. Therefore, the effects of their study can be explained.

Importance of astrology in daily life

The importance of astrology can be clearly seen in our daily life. We get the knowledge of Teej-festivals, festivals, festivals etc. only through astrological calculations. The vast influence of astrology can be

seen in the rural life of India, that is why even an illiterate farmer knows which constellation has good rainfall. When should they sow the seeds? With the use of astrology, the troubles in life can be reduced, the obstacles of life can be removed. More success can be achieved with less effort.

.

If you plant plants according to your zodiac, planet or constellation, it will be of great benefit and the problem will be solved. Happiness will increase.

Every person is born in one or the other constellation of the zodiac. Each planet, zodiac and constellation has a representative tree. Knowing the tree of constellations, planets and zodiac signs here, if you plant it in the right place around your house, then you will get its benefit. When these plants grow, your planetary constellations will be correct. However, which tree or plant you should plant, please consult an astrologer or Vastu Shastra. Take care of the day and Muhurta.

By zodiac signs:

1. Aries: Kochila, Amla, Gulhad and Khadir or Khair.
2. Taurus: Gulhad, Jamun, Khair and Gular.
3. Gemini: Khair, Sheesham, Bamboo and Apamarga
4. Cancer: Bamboo, Peepal, Nagkesar and Palash.
5. Leo: Butt, Palash, Pakad and Ank.
6. Virgo: Pakad, Reetha, Bel and Durva.
7. Libra: Bel, Arjun, Kataya, Bakul and Gular.
8. Scorpio: Kataiyya, Moulshree, Chir and Khadir.
9. Sagittarius: Shawl, Ashok, Jackfruit and Peepal.
10. Capricorn: Jackfruit, Akon and Shami.
11. Aquarius: Shami, Kadamba and Mango.
12. Pisces: Mango, Neem, Peepal, Mahua and Kush.

According to the planets

1. Sun: Madar tree.
2. Saturn: Shami tree, kikar, aak, date palm are also there.
3. Rahu: Durba grass, coconut tree or sandalwood tree.
4. Ketu: Kusha tree, tamarind tree, sesame plant and banana tree.
5. Moon : Palash or poppy tree.
6. Mars: Neem, Dhak or Khair tree.
7. Mercury: Apamarga tree, banana or broad leaf plant.
8. Jupiter: Paras Peepal, Peepal or Banana tree.
9. Venus: Sycamore tree, cotton plant and vineyard plants like money plant.

भारतीय संस्कृति

पर्यावरण में गाय का गोबर सहायक

हिंदू धर्म को मानने वाले गाय में माता का स्वरूप देखते हैं।

सुरभि तोमर

प्राचीन काल से ही 'गाय, गंगा और गायत्री' भारत की पहचान बनी हुई हैं। यदि किसी दिन इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो भारत का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। गोवंश की सेवा करना हमारी पुरातन परंपरा रही है। भारतवर्ष में संत समाज, समाज सेवी संघ और भारत के करोड़ों आम लोग तन मन धन से गौमाता की सेवा करते आ रहे हैं। गोवंश की हत्या पर कड़ा प्रतिबंध लगाने और इनके संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने और परिणामदायक प्रयास करने की मांग भी अक्सर उठती रहती है।

हिंदू धर्म को मानने वाले गाय में माता का स्वरूप देखते हैं, जो उनका मां की भांति ही पालन पोषण करती है। पुराणों में वर्णित है कि हम गौमाता के जितना समीप रहेंगे, उतना ही स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव गाय के मूत्र और गोबर का उपयोग कीटनाशक और अन्य औषधि बनाने में कर रहे हैं। उनका कथन है कि, "इन उत्पादों को अपनाइए, गौमाता को बूचड़खाने में में जाने से बचाइए"। वर्तमान में वायु प्रदूषण हमारे समक्ष बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। देश में प्राकृतिक ऊर्जा और पर्यावरण की रक्षा करना, उन्हें संरक्षित करना, हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। प्रदूषित वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए यह आज की आवश्यकता बन गई है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने में गाय का गोबर सहायक हो सकता है। कैसे, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं।

भारतीय संस्कृति में वृक्षों में भी जीवन होने को मान्यता मिली है। भारतीय सनातन धर्म में प्रत्येक जीवात्मा का सम्मान करने की भी शिक्षा दी गई है। हिंदू धर्म, यह कहना चाहिए हिंदू जीवन पद्धति में बरगद, पीपल, तुलसी आदि अन्य वृक्षों की पूजा करने का विधान है। वृक्षारोपण करना और वृक्षों को काटने से बचाना हमारी "पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों" की अहम कड़ी है। लेकिन चाहे विकास के नाम पर हो या फिर ईंधन की आवश्यकता पूर्ति के लिए या फिर शवों की अंत्येष्टि क्रिया कर्म के लिए, चिता दहन के लिए वृक्षों का बहुतायत से कटना जारी है। धड़ाधड़ वृक्ष काटे जा रहे हैं। वृक्ष नहीं तो वर्षा नहीं, हम इससे अनजान नहीं हैं। दिन होने और वर्षा जल के अभाव में भूमंडल के तापमान में वृद्धि होने का भी हमें ज्ञान है। हिम खंडों का अचानक गिरना, बेमौसम की तूफानी बरसात, समुद्र स्तर का बढ़ना, तीव्र ठंड या गर्मी का होना जैसे कई दुष्परिणामों को हम झेल रहे हैं। इन सभी समस्याओं का कुछ समाधान अधिक संख्या में वृक्ष लगाने और वृक्षों को ना काटने से हो सकता है। इसके लिए लकड़ी का विकल्प ढूंढना आवश्यक है। गाय का गोबर लकड़ी का अच्छा विकल्प बन सकता है। प्राचीन समय में भी गोबर के उपले बनाकर उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। साधु संतों की धूनी रमाते थे, जो आराधना करने का एक प्राचीनतम रूप था। इससे वातावरण की भी शुद्धि होती है और सात्विकता का भी अनुभव होता है।

गांवों में शाम के समय मच्छरों तथा अन्य कीटों को भगाने के लिए गाय के गोबर से बने कंडों से धुआं किया जाता रहा है। क्यों ना एक बार फिर से हम गाय के गोबर का उपयोग करने लगे? यह एक विचारणीय विषय है। समय के साथ तकनीक में सुधार होता गया। आजकल गोबर को मशीन में दबाव डालकर 'गोबर काष्ठ' बनाया जा सकता है। जो लकड़ी का बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है, हम होलिका दहन के लिए ईंधन के रूप में तथा अलाव जलाने में इन गोबर काष्ठ का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान करने तथा भावनात्मक कारणों से भी शवों का दाह संस्कार विद्त दाह द्वारा करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए गाय के गोबर से बना काष्ठ उपयुक्त विकल्प रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में पहले से ही सबको कंडों पर जलाने की प्रथा रही है। गोबर काष्ठ का उपयोग किए जाने से गौधन का महत्व बढ़ेगा, वह बूचड़खाने में जाने से बचेंगी। साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो सकेगी।

गाय के गोबर का उपयोग गोबर गैस प्लांट में भी किया जाता है। अब अपनों के स्थान पर गोबर गैस का उपयोग किया जाने लगा है, जो धुएं आदि की समस्या से रहित और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। आज कल गैस और बिजली संकट आम बात है। ऐसे में गांवों में गोबर गैस के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कोयला, एलपीजी गैस, पेट्रोल तथा डीजल महंगे होने के साथ-साथ प्रदूषण भी फैलाते हैं। अक्सर

कौन काम लाभार्थ है, कौन काम परमार्थ गौपालन लाभार्थ है, गौसेवा परमार्थ

इनकी आपूर्ति भी बाधित होती रहती है। बायोगैस का स्रोत कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जब तक गौधन यानी गौवंश रहेगा, हमें यह ऊर्जा मिलती रहेगी।

एक गाय के गोबर से वर्ष भर में लगभग 45000 लीटर बायोगैस बन सकती है। बायोगैस का उपयोग करने से 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी बच सकती है, जो अभी तक जलाई जा रही है। इससे 14 करोड़ वृक्ष कटने से बचेंगे और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। वृक्षों का एक प्रमुख कार्य कार्बनडाइऑक्साइड का अवशोषण करना है। वृक्ष कार्बनडाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 14 करोड़ वृक्षों द्वारा 3 करोड़ टन उत्सर्जित कार्बनडाइऑक्साइड को सोखा जा सकता है। साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। इसके अलावा गोबर गैस संयंत्र में गैस प्राप्ति के बाद बचे अवशेष को जैविक खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। गोबर की खाद खेत के लिए अमृत का काम करती है। कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। फसल का उत्पादन अधिक होता है और पैदा होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। रासायनिक खादों के उपयोग से पैदा हो रहे अन्न या अन्य उत्पाद जैसे फूल, सब्जी इत्यादि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को निरंतर कम करते रहते हैं।

पुराने समय में गाय का गोबर घरों की दीवारों और फर्श लीपने के काम आता था। गोबर कीटाणुनाशक का कार्य करता है। इससे मकड़ी छिपकली तथा अन्य कीड़े मकोड़ों से बचाव होता था। क्योंकि घर का फर्श सप्ताहिक रूप से लीपा जाता था, इससे हमें एक सात्विक एहसास भी होता था कि घर पूर्णतया स्वच्छ हो गया है। गोबर का एक और गुण है यह रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता

है। आणविक विकिरण से मुक्ति पाने के लिए जापानियों ने गोबर को अपनाया। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी ई बीगेडन ने गोबर पर अनेक प्रयोग किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे की गाय के ताजे गोबर से टीबी तथा मलेरिया के जीवाणु भी मर जाते हैं। त्वचा संबंधी रोगों जैसे दाद, खाज, एग्जिमा तथा घाव आदि के लिए गोबर लाभदायक होता है।

गाय हिंदुओं के लिए मां के समान होती है, वह पूजनीय है। शास्त्रों में गऊ हत्या को ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। लेकिन विदेशी इतिहासकारों तथा मार्क्सवादी विचारधारा के भारतीय इतिहासकारों ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में आर्य गौमांस खाते थे। यह बिल्कुल निराधार एवं असत्य है। संस्कृत भाषा में एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह कहां पर और किस कारण प्रयुक्त हुआ है, उस सांस्कृतिक परिवेश में समझना होता है। किंतु मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, चिंतकों ने वैदिक धर्म शास्त्रों में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का सतही अर्थ निकाल कर भ्रांति फैलाई। हमें इन्हें

योग गुरु बाबा रामदेव गाय के मूत्र और गोबर का उपयोग कीटनाशक और अन्य औषधि बनाने में कर रहे हैं। उनका कथन है कि, "इन उत्पादों को अपनाइए, गौमाता को बूचड़खाने में में जाने से बचाइए"।

सही अर्थों में समझने और अन्य को समझाने की आवश्यकता है। यह समय की मांग है की गौवंश की हत्या के विरुद्ध और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के लिए हम सब एकजुट होकर आवाज उठाएं, ताकि हम अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की भी रक्षा कर सकें।

जल ही जीवन है

दम तोड़ती नदियों को बचाने की गुहार

नदियों में औद्योगिक अथवा किसी प्रकार भी कचरा डालने से बचा जाए।

राजी सिंह

नदियां प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों में आती हैं। इन पर ही जनजीवन और उनसे जुड़ी आवश्यकताएं निर्भर है। भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन भारत में नदियों को बहुत महत्व दिया गया है। उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इन्हें देवी देवता और मां की संज्ञा दी गई है। हमारे पूर्वजों ने नदियों से इतिहास, वर्तमान और भविष्य की कल्पना की और जीवन में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। नदियों से ही सभ्यता और प्रगति के मार्ग की नींव रखी गई। विश्व की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली और विकसित हुई। नदियों की विवेचना करने, उन को परिभाषित करने में भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है, किंतु मानव जीवन के लिए नदियों के महत्व को दोनों ने ही स्वीकार किया है।

नदियां भारत की हो या विश्व के किसी अन्य देश की, हमने विकास के नाम पर उनका गला घोंटने का ही काम किया है। भारतीय संस्कृति में नदी का पूजनीय स्थान था, किंतु पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध और आकर्षण में हम नदियों का अस्तित्व और उनका महत्तव भूलते चले गए। नदियों का अर्थ केवल सिंचाई के साधन, ऊर्जा के स्रोत तथा गंदगी कूड़ा करकट बाहर ले जाने वाली जलधारा के रूप में बन गया। नदियों के प्रति पूजनीय योग आस्था का भाव विलुप्त हुआ तो वह केवल भोग्य रह गई। उनका दोहन होने लगा, शहर भर की गंदगी उनमें बहाई जाने लगी। नदियों के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण उनकी दुर्दशा का कारण बनता चला गया।

कहने को तो हम लंबी चौड़ी बहस करते हैं नदियों के महत्व पर तरह-तरह के तर्क देते हैं कि 'जल ही जीवन है', 'जल बिन सब सून', 'नदी बिन जीवन संभव नहीं' 'नदियों से मानव की समृद्धि जुड़ी है', जैसे बड़े-बड़े प्रिय नारे लगाए जाते हैं। लेकिन हमारी अधिकांश चिंता मात्र विमर्श या लोक लुभावने नारे तक ही सिमट कर रह जाती है। यथार्थ के धरातल पर अधिकतर उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जाता, एक दो अपवाद को छोड़ दें तो सभी जगह यही हाल है। जब की आवश्यकता नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए गंभीर कदम उठाने की है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि नदियों के अस्तित्व के मिट जाने का अर्थ है हमारे स्वयं के जीवन को संकट में डाल देना नदियों को बचाने का आशय है। मानव जीवन को बचा लेना विश्व में सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने अपनी वांगनुई नदी व मनुष्य का जीवन का दर्जा दिया। उसके इस निर्णय को सर्वत्र सराहा गया?

भारत ही नहीं आज समस्त विश्व की नदियां संकटग्रस्त है। जिन नदियों का उद्गम स्थल हिमखंड है, जैसे गंगा यमुना आदि के सदा सलिल बनी रहती है और उस समय तक बनी रहेगी, जब तक हिमखंड पूरी तरह पिघल नहीं जाते। दूसरी तरह की नदियां वर्षा नदियां हैं, जो पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर हैं। इन नदियों पर भारी संकट है। इसका सबसे बड़ा कारण है वन क्षेत्र का घटना। विश्व में 40 बड़े जलागम क्षेत्र हैं, जो विश्व के 50% ही पानी के कारक हैं। गत कुछ वर्षों से इस में 40% की गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण है विकास के नाम पर इन जलागमों के 50% से अधिक वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है, वनों के क्षतिग्रस्त होने से हवा में मिट्टी और जल का क्या नुकसान होगा

समझा जा सकता है।

दरअसल वन वर्षा के नियंत्रक होते हैं। नदियों के जलागमों से वनों के नष्ट हो जाने के कारण मानसून के मौसम में नदियां बाढ़ से उफनने लगती हैं और अन्य मौसमों में विलुप्त हो जाती हैं। नदियों के विषय में जब भी कोई चर्चा होती है, वह उनके प्रदूषण को लेकर होती है। नदियों के प्रवाह को लेकर अक्सर चर्चा नहीं की जाती। यदि नदियों में गति बनी रहेगी, उनका प्रवाह अभाध गति से होता रहेगा तो वह स्वयं को प्रदूषण मुक्त रखने की क्षमता रखती है। जब बांध निर्माण या ऐसे ही अन्य किसी कारण से उनका प्रवाह बाधित होता है, तो प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है। कौन सी नदी कितनी सक्षम है। इसकी परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि उस नदी का मानसून और अन्य मौसमों में प्रवाह का अनुपात क्या रहता है। अच्छी सक्षम नदी में यह अनुपात 1:7 रहता है। इसका अर्थ है कि सामान्य मौसम की तुलना में मानसून में अधिक से अधिक 7 गुना पानी होना चाहिए। जो वर्तमान में 1:70 रहता। इसका तात्पर्य है कि वन्य विहीन होने से जलागमों में वर्षा जल रोकने की क्षमता नहीं रही है और इसी कारण नदियों में बाढ़ आती है।

नदियों के अस्तित्व पर संकट का एक और प्रमुख कारण है, प्रदूषण। नदियों के प्रति हमारी बेरुखी के कारण कारखानों की गंदगी गंदे नाले तथा अन्य सभी तरह का कूड़ा कचरा नदी में बहाया जाने लगा और नदियां मैला ढोने वाली जल धाराओं में बदल गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि देश की आबादी से ज्यादा नदियां पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। आज एक भी नदी ऐसी नहीं है, जिसे पूरी तरह स्वस्थ और स्वच्छ कहा जा सके। देश में 9 नदी तंत्र हैं, जो देश के 81% भूभाग पर फैले हैं। इनसे प्रति व्यक्ति 1720.29 क्यूबिक मीटर पानी वार्षिक मिलता है, लेकिन तेजी से

देश में 9 नदी तंत्र हैं, जो देश के 81% भूभाग पर फैले हैं। इनसे प्रति व्यक्ति 1720.29 क्यूबिक मीटर पानी वार्षिक मिलता है, लेकिन तेजी से बढ़ते प्रदूषण से यह आंकड़ा कम हो जाएगा।

बढ़ते प्रदूषण से यह आंकड़ा कम हो जाएगा। देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां में घग्गर है, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। दिल्ली की शान कहीं जाने वाली यमुना नदी की गिनती अब सबसे प्रदूषित नदियों में की जाने लगी है। गंगा पर केंद्र सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है, अच्छे परिणाम भी दिखने लगे हैं। अभी तक गंगा विश्व की सबसे 5 अधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जा रही है। नदियों का इस तरह प्रदूषण से अवरुद्ध हो जाना ऐसे ही है, जैसे शरीर की धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। इसे अत्यंत खतरनाक स्थिति में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है और जल ही जीवन है।

भारत की नदियां ही नहीं विश्व की प्रमुख नदियों की स्थिति भी अत्यंत भयावह है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्सी सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्र में ढोकर ले जाती है। चीन की ऐलो नदी में 4.29 अरब टन औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज गिरता है। इटली की सारणी यूरोप में सबसे गंदी नदी बन चुकी है। अमेरिका की मिसिसिपी 12 सौ करोड़ टन कचरा ढ़ो रही है। इससे जुड़ी मिसीसिपी घाटी में खेती-बाड़ी खतरे में है। इस घाटी को अब हेड ओजोन कहा जाता है। इंडोनेशिया कि सिस्टम नदी में इतना कचरा पड़ चुका है कि पारे का स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। पारे का स्तर 100 गुना बढ़ गया है। इजराइल की गार्डन नदी समेत सभी नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं।

हमें यह बात समझनी ही होगी कि मानव जीवन की उत्पत्ति ही पानी

"हिमखंडों से पिघलकर, पर्वतों में निकलकर खेत खलिहानों को सींचती, कई शहरों से गुजरकर अविरल बहती, आगे बढ़ती बस अपना गंतव्य तलाशती मिल जाने मिट जाने, खो देने को आतुर वो एक नदी है।"

से हुई है। यदि पानी ही नहीं बचा, तो जीवन भी नहीं बचेगा। अतः आवश्यक है कि जलागम पर क्षेत्रों का विस्तार किया जाए। वृक्षारोपण बड़े स्तर पर किया जाए। नदियों में औद्योगिक अथवा किसी प्रकार भी कचरा डालने से बचा जाए। सरकार एवं नागरिक, समाज में अपने अपने स्तर पर नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कारगर उपाय करें। सिर्फ आंदोलन के नाम पर दिखावटी बहस और विमर्श से काम नहीं चलेगा। धरातल पर कुछ ठोस कार्य करने होंगे ताकि हमारी कराहती नदियों को जीवन दिया जा सके।

प्राकृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन

ऐसा कतई नहीं है कि स्थिति केवल पहाड़ों पर ही खराब है।

कुलदीप नागेश्वर पवार

बीते दिनों हिमाचल के किन्नौर और सिरमौर में घटी तबाही की तस्वीरें गवाह है कि, "मर्यादाओं को लांघने पर, पहाड़ भी धैर्य खो देते हैं।" लेकिन शायद मनुष्य हर बार की तरह इसे लगातार नजरअंदाज कर रहा है, ठीक केदारनाथ त्रासदी 2013 की तरह। प्रकृति के साथ मानव समाज का ये असंवेदनशील रवैया और खुद को ओर अधिक आरामदायक जीवनशैली देने की उसकी भूख जिसे वह विकास का नाम देता है, देखा जाए तो वही इस मानव सभ्यता के विनाश का पर्याय बनती जा रही है। कुछ पर्यावरणविद् और प्रकृति प्रेमी इन मौजूदा स्थितियों को लेकर चिंतित भी हैं और इसकी बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत भी, लेकिन उनके प्रयासों को वास्तविकता में देखे तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान जान पड़ते हैं। विश्वास है इस कथन को प्रकृति पुत्र इस दृष्टि से देखेंगे कि हमें अपने प्रयासों की गति और संख्या दोनों में वृद्धि की आवश्यकता है।

पिछले ही दिनों हिमाचल प्रदेश के मनाली का एक वीडियो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक सुर्खियों में रहा। जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद हुए अनलॉक से पर्यटकों के एक हुजूम के पहाड़ों की ओर टूट पड़ने का भयावह दृश्य था। इस बार सभी को ये चिंता थी कि इस भीड़ से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा ओर अधिक बढ़ सकता है। लेकिन इससे कई ज्यादा संवेदनशील बिंदू 'पर्यावरणीय अनुकूलता' को कोई देखना ही नहीं चाह रहा था और कुछ लोग जो पहाड़ों की प्रकृति से परिचित हैं, वे लॉकडाउन की आर्थिक तंगी की मार के चलते इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे।

लेकिन एक शाश्वत सत्य ये भी है कि प्राकृतिक घटकों के उपभोग की भी एक सीमा होती है और पहाड़ी क्षेत्र अन्य बाकी क्षेत्रों की तुलना

में अधिक संवेदनशील होते हैं। जहां पर अधिक शोर या भीड़ इन प्राकृतिक घटकों को क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। प्रकृति अपनी शांत प्रवृत्ति में अधिक मनमोहक लगती है और निसंदेह ही मनुष्य इसी सुंदरता को निहारने पहाड़ों की ओर जाता है। मनुष्य का शांति के लिए पहाड़ों की ओर जाना प्राचीन समय से ही सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन समय के साथ बढ़ती सुविधाओं और मनुष्य की बदलती प्राथमिकता ने इस शांति मार्ग की यात्रा में कई अवरोधों को उत्पन्न किया है। आज पर्यटक पहाड़ों पर स्वयं के आनंद के सामने इन प्राकृतिक घटकों की अनुकूलता को गौण समझते है। जिसका खामियाजा पहले यहां के स्थानीय रहवासियों को और बाद में पूरी मानव जाति को उठाना पड़ता है। याद रहे इस नुकसान का कोई एक स्वरुप तय हो ऐसा नहीं है, ये हवा,पानी, मिट्टी और अब तो संस्कृति को भी दूषित करते जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसे हम उसकी गंभीरता को जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं।

ऐसा कतई नहीं है कि स्थिति केवल पहाड़ों पर ही खराब है। जैसे-जैसे हम पठारीय राज्यों की ओर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे प्रदूषण का

“पर्वत, पठार और मैदान, सब की खूबसूरती पर हावी होता इंसानी विकास।”

काला साया ओर भयानक रुप में दिखाई पड़ता है। और इसे लेकर लोगों की लापरवाही ओर अधिक बढ़ जाती है, जैसे मानों ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो लॉकडाउन के दौरान इन क्षेत्रों में जितनी तेजी से प्रदूषण में कमी देखी गई थीं, सबकुछ अनलॉक होने के बाद हालत उतनी ही तेजी से बिगड़े हैं। इन क्षेत्रों में लगे कल-कारखानों की नियमावली में तो पर्यावरण के प्रति गंभीरता देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत से आप और हम बखूबी परिचित हैं। फिर चाहे आप इन क्षेत्रों में बहती मां गंगा को देख लीजिए या फिर यमुना को।

जो घट चुका है, घट रहा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भविष्य के गर्भ में है, जो घटने वाला है, वो मानव और प्रकृति के हित में हो इतना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे एक प्राकृतिक साधना के रुप में भी देखा जाना चाहिए। इस साधना में मानव को वर्षों का धैर्य रखने के साथ एक संयमित जीवनशैली को अपनाना होगा। जैसे कि पहाड़ों की यात्रा पर सीमित संख्या में लोगों को जाने की व्यवस्था वर्तमान स्थिति की जरुरत मालूम होती है और इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला शासन पर निर्भर है, इसलिए हम इसे यहीं छोड़, स्वयं जो हम से हो वो करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि-

* अपशिष्टों को खुले में न फेंक उनके निस्तारण की उचित व्यवस्थाओं प्रयोग में लाएंगे।

* प्लास्टिक, पॉलीथिन का उपयोग नहीं या कम से कम करेंगे, कपड़े के थैले को प्रचलन में लाएंगे।

* वृक्षारोपण के नाम पर फोटो खिंचवाने की होड़ से इतर लगे हुए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी लेंगे।

* अपने विशेष दिवसों पर प्रकृति हितैषी अनुप्रयोग का अनुसरण करेंगे व उनके लिए वचनबद्ध रहेंगे, जिसके विविध माध्यम आज उपलब्ध हैं।

* किचन गार्डन और वर्मी कम्पोस्ट जैसी तकनीकी को अपनाएं एवं जन-जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें।

* अपने आवास में ही कहीं मूक पक्षियों के लिए आश्रय स्थल बनाकर उनके दाने-पानी की व्यवस्था कर दें।

*

“मर्यादाओं को लांघने पर, पहाड़ भी धैर्य खो देते हैं।”

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिसाइक्लिंग, हलमा जैसी युक्तियों को अपनाकर इसे प्रचारित करें।

* खाली समय में बच्चों, युवाओं व अन्य सभी को पर्यावरण व मानव उत्थान के इस महायज्ञ में अपनी आहुति कर्म देने के लिए प्रेरित करें एवं परिवेश में फैली इससे जुड़ी भ्रांतियों को कम करने को लेकर प्रयास करें।

* अंत में महत्वपूर्ण ‘पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए कृतज्ञ लोगों को समाज में सम्मान दें, ताकि उनसे अन्य लोग प्रेरणा ले सकें।’

जल्द हम नए विचारों के साथ इस पर्यावरण यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगें।

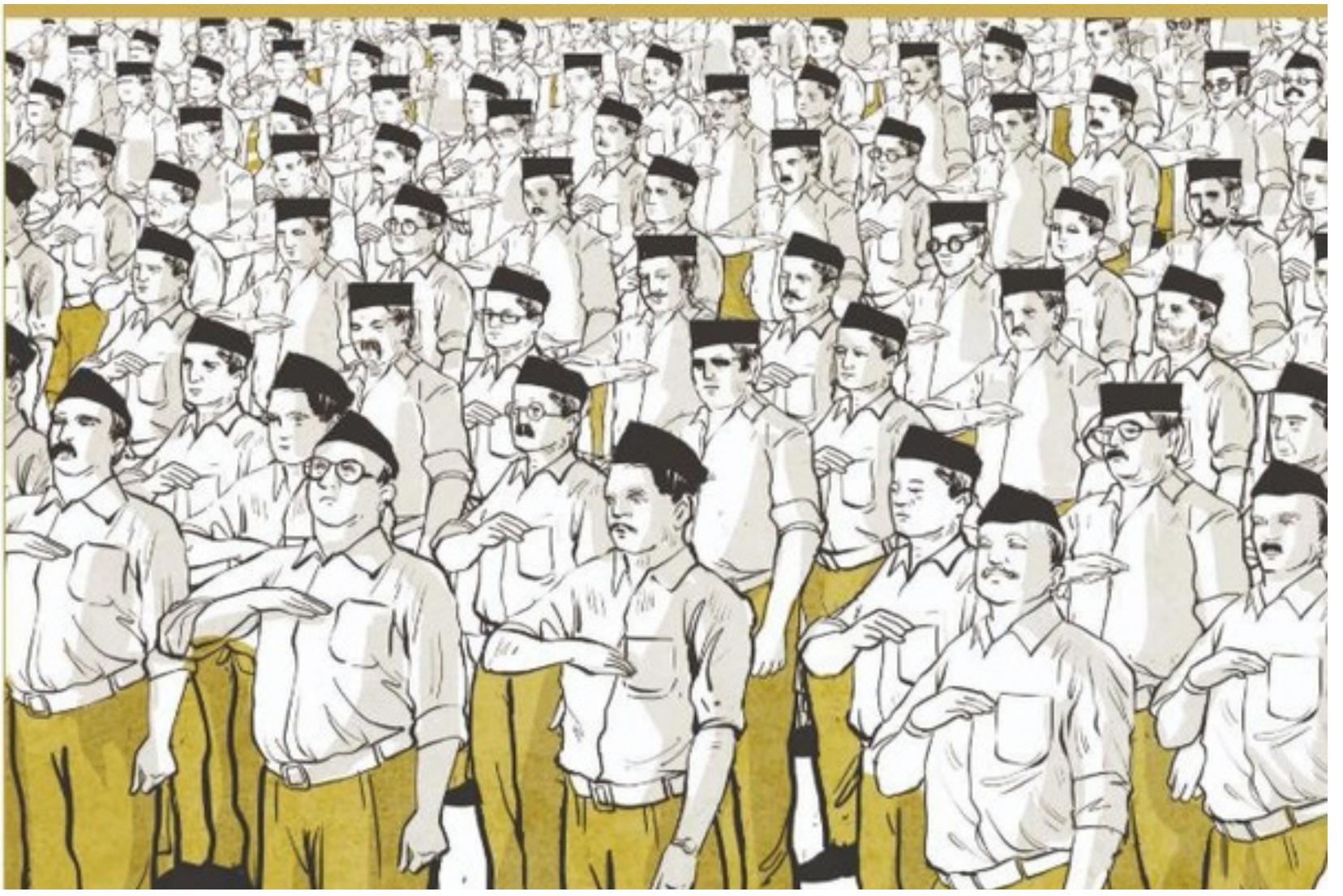

राष्ट्रीय आपदा

स्वयंसेवक संघ का सेवाधर्म

यह कोई पहला अवसर नहीं था जब संघ समाज के हर तबके के साथ खड़ा रहे।

डॉ. सौरभ कुमार मिश्र

प्रस्तावना

चीन के वुहान से निकलकर पूरे वैश्विक पटल पर पिछले डेढ़ साल में सभी को निशाना बनाते हुए चाइनीज वायरस कोविड 19 ने हर ओर हाहाकार मचा दिया। नवम्बर 2019 से ही विश्वभर में इसका विभत्स रूप देखा गया। जहाँ स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ भावनात्मक रिश्तों ने भी दम तोड़ रहे हैं। इसके प्रकोप से विश्व भर में लाखों लोगों को असमय ही जान से हाथ धोना पड़ा। तो कितने इसकी चपेट में आकर तिल-तिल जीने को मजबूर हुए। पूरे विश्व में त्राहि-त्राहि का माहौल व्याप्त रहा। इसका प्रभाव भारत के सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि पर गहरे से देखा गया। लेकिन चाइना से शुरू हुए इस वायरस की मूल उत्पत्ति की वास्तविकता पर ध्यान दें तो यह संकट मानव की भोगवादी प्रवृत्ति, विलासितापूर्ण जीवन, अनियोजित तथा अनियंत्रित विकास की शोषणपरक नीति की देन है। हमने जिस तरह से प्रकृति के जीवनचक्र से छेड़छाड़ की उसी का खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। कथित विकास की आड़ में मनुष्य ने जिस तरह से प्रकृतिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है उसकी सजा तो हम सबको भुगतनी ही थी। यह संकट जिसने पूरे विश्व को क्षति पहुचाई स्पष्ट रूप से चीन की देन है। इसलिए अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित

94 वषा क दारान सघ हमशा दश म आने वाली आपदाओं और संकटकाल में समाज की मदद के लिए आगे आता रहा है।

अनेक देशों ने इसे चाइनीज वायरस का नाम दिया। धरती पर मौजूद जो कुछ भी है वो सब कुछ खा जाने की प्रवृत्ति ने चीन को संपूर्ण विश्व के तमाम देशों को परेशानी में डाल दिया। शायद यह इस सदी का सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि स्वास्थ्य के साथ-साथ पूरी दुनिया को बड़े आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा।

यह एक ऐसी आपदा है जो इस सदी में सभी के लिए एक नई चुनौति के रूप में है। लेकिन वैज्ञानिकों, डाक्टर्स ने इस चुनौती को झेलते हुए इसेक टीके की खोज की। जिसने कहीं ना कहीं लोगों को हिम्मत प्रदान किया। लेकिन इस सबके अलावा समाज में एक बड़ा वर्ग था जिसने अपने स्वास्थ्य व जानमाल की फिक्र किए बिना सिर्फ समाज की सेवा में अनवरत लगे रहे। इसमें से एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ ने इस आपदा रूपी तूफान में डटे रहकर यह साबित कर दिया कि भारत भू पर जब-जब कोई विपत्ति या आपदा आएगी वे पूरी ताकत के साथ इसका सामना कर इस पर विजय भी हासिल करेंगे। यह कोई पहला अवसर नहीं था जब संघ के स्वयंसेवक मजबूती से समाज के हर तबके के साथ खड़े रहे। विगत 94 वर्षों में ऐसे कई अवसर अए जब स्वयंसेवकों ने सेवाधर्म के नए प्रतिमान गढ़े हैं।

शायद यही भाव है जो आज जब पूरा विश्व एक अदृश्य चाइनीज वायरस कोरोना से संघर्ष कर रहा है, तो सेवाभाव का ही परिणाम है कि समाज के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों को इससे बचाने के लिए संघ इसके प्रकल्प और स्वयंसेवक पूरी जिम्मेदारी व अपनत्व के साथ आपने आपको आगे ला रहे हैं। कितने ही इससे संक्रमित हो गए, कितनों की मौतें हो गईं। लेकिन समाज कल्याण व राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को जीवंत करता यह संगठन व इसके स्वयंसेवक दिनरात सेवा में लगे हुए हैं। कोई भोजन वितरण में, कोई सेनेटॉइजेशन में, दवा वितरण में, मास्क वितरण, धन संग्रह, रक्तदान जैसे सभी जरूरी कार्यों में अपने आप को तैयार किए हुए हैं। क्योंकि संघ की भावना वसुधैव कुटुम्बकम् की है जिसे लेकर सभी स्वयंसेवक अपना कार्य करते हैं। आज भी इस संकटकाल में अपनी पूरी तत्परता तथा निष्ठा के साथ आर.एस.एस. के सभी प्रकल्प व स्वयंसेवक अपना कार्य कर रहे हैं और करते भी रहेंगे।

राष्ट्रीय आपदाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवाभाव

हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। साथ ही उसका चिन्तन में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना निहित है। हम एक विशाल परिवार के सदस्य हैं। इन भावों को अंतःकरण में जगाते हुए ट्सेवा' ही समाज का स्वभाव बने। सेवा एक आंदोलन बने। ऐसा प्रयास करना, आज की सामाजिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में डॉ. के. हेडगेवार जी के समय से ही सेवा की परंपरा अविरल चली आ रही है। संघ संस्थापक पू. डॉ. हेडगेवार जी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई करते समय 1913 में बंगाल की दामोदर नदी में आई बाढ़ तथा गंगासागर क्षेत्र में पीड़ितों की जो सेवा की थी। आज की स्थिति में सेवा के इसी भाव को लेकर स्वयंसेवक समाज में कार्य कर रहे हैं। संघ स्थापना के बाद देश में कई आपदाएँ आई। इसमें स्वयंसेवक तन-मन-धन से लगे व समाज को इससे उभारने का प्रयास किया। ऐसे ही कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

सन् 1947: त्याग और सेवा की गाथा

मार्च सन् 1947 में रावलपिंडी में जो मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे, उनके कारण लाखों हिन्द बेघर हो गए थे। विभाजन के बाद भी वह बराबर होता रहा। एक समूची जाति को उजाड़ दिया गया, उखाड़कर फेंक दिया गया। अनगिनत लोगों की हत्या हुई, उनके अंग-प्रत्यंग काट दिए गए तथा उन्हें अपमानित किया गया। चारों ओर विवशता और नैराश्य का घोर अंधकार था। ऐसे में उन पीड़ितों को लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आशा की वह एकमात्र किरण है जो उन्हें सांत्वना और सहायता प्रदान कर सकती थी। स्वयंसेवकों ने ट्पंजाब सहायता समिति' का गठन किया और प्रान्त की हर तहसील में शिविर खोल दिए। इस निमित्त धन के लिए श्रीगुरुजी के अनुरोध का लोगों ने मुक्त हृदय से स्वागत किया। पचास लाख रुपये से भी अधिक की राशि एकत्र की गई। उससे सहायता शिविर चलाए गए।

वनवासी गांवों का पुर्निर्माण

मुलापल्म का समूचा गाँव जल में विलीन हो गया था। संघ के कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्ली के सहयोग से एक आदर्श बस्ती के रूप में उस गाँव का पुनर्निर्माण किया। यह ग्राम अब दीनदयालपुरम् के नाम से जाना जाता है। 110 घरों का यह गाँव पक्के आरसीसी आकल्पन (डिजाइन) का है। गाँव वालों के लिए पीने के पानी और वैज्ञानिक आधार पर बने सामूहिक शौचालयों की व्यवस्था की गई। दीनदयालपुरम् के अतिरिक्त तीन और गाँवों का पुनर्निर्माण किया गया। गुण्टूर जिले में केशवपुरी ग्राम में आदवी बनादीस नामक वनवासियों का पुनर्वास किया गया। कृष्णा जिले के माधवनगर ग्राम में अनुसूचित जाति के लोगों को पुनः बसाया गया। तीसरा गाँव विशाखापट्टनम् जिले में श्रीरामनगर है। वहाँ जितने भी लोगों का पुनर्वास किया गया, वे सभी अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हैं। श्रीरामनगर प्रकल्प के बारे में दिनांक 13 जुलाई 1979 के 'हिन्द' में समाचार छपा 'विशाखापट्टनम् की संघ शाखा सहायता कार्य में जुटे हैं।

भोपाल गैस त्रासदी और संघ का सेवाभाव (1984)

झीलों की नगरी भोपाल में 3 दिसम्बर 1984 का दिन वर्तमान युग के मानव जीवन के लिए सर्वाधिक त्रासदी का दिन था। उस दिन एकदम सबेरे मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के संग्रहण टैंक में उग्र रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लगभग 40 टन अति विषैली गैस 'मिथाइल आइसो साइनेट' रिसकर वातावरण में फैल गई। हमीदिया अस्पताल गैस पीड़ितों से भर गया, पर उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंध पूर्णतया ठप्प हो गए थे। स्वयंसेवकों ने इसमें नगर निगम का हाथ बँटाया और इन प्राथमिक आवश्यकताओं को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया। बेकार पड़े शौचालयों का सुधार और पुनरुद्धार किया गया। पीड़ित परिवारों के सम्बन्धियों को खोजने और उन्हें एक साथ करने के प्रयास किए गए। स्वयंसेवकों ने शवों की पहचान में हर परिवार के लोगों की सहायता की और समुचित दाह संस्कार के लिए प्रबंध भी किए।

लातूर का विनाशकारी भूकंप (सन् 1993)

सन् 1993 में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों के कुछ

अंचलों में आया भूकंप भीषणतम भूकंप था। इस भूकंप की चपेट में आकर लगभग 15,000 लोग मारे गए। क्षेत्र के 113 गाँव लगभग विनष्ट हो गए। इस विभीषिका से 38,000 परिवार प्रभावित हुए तथा 800 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि हुई। अन्यत्र आए संकटों की भाँति इस महान विपदा में भी यह देखने में आया कि विपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए संघ के स्वयंसेवक सब ओर से दौड़े आए। देशभर में सहायता के लिए नकद अथवा वस्तुओं के रूप में 5.12 करोड़ रुपये राशि एकत्र की गई थी। ब्रिटेन के सेवा इंटरनेशनल तथा हिन्द स्वयंसेवक संघ ने घर-घर अभियान चलाया तथा अनेक स्थानीय धार्मिक, सामाजिक और वाणिज्यिक संस्थाओं के सहयोग से 1.75 करोड़ रूपये भेजे।

सुनामी में सहायता कार्य

जापान में बार-बार उठने वाला अत्यन्त खतरनाक सुनामी नामक तूफान पूरे वेग से भारत के दक्षिणी तट पर टकराया जिससे जान-माल की अपार क्षति हुई। ऐसी विकट परिस्थिति में उनकी सहायता में पहुँचने वाले सर्वप्रथम समूहों में अ.भा.वि.प. के कार्यकर्ता भी शामिल थे। चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने 12,000 भोजन पैकेट, 40,000 हजार पानी पैकेट और 20 बड़े कॉर्टून कपड़ों का वितरण किया। 4 जिलों के 200 कार्यकर्ता नागपट्टनम् गए और सेवाभारती के साथ मिलकर राहत एवं सेवाकार्य में हाथ बँटाया। मदुराई में दो लॉरी खाघ सामग्री, दवाएँ, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि पदार्थ सुनामी पीड़ितों को उपलब्ध कराए गए। पूरे प्रदेश में अभाविप कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य का अनुपम उदाहरण पेश किया। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2001 को सबेरे-सबेरे धरती काँप उठी और देखते-ही-देखते कच्छ और भुज का सारा क्षेत्र श्मशान में परिवर्तित हो गया किन्तु उसमें भी अभाविप के बहुत से कार्यकर्ता अपने परिवार की चिंता छोड़ अपने छात्र मित्रों को साथ लेकर लोगों की सहायता में जुट गए। बिना देर किए शवों के निष्पादन और दाह संस्कार के कार्य पूरे किए।

ऐसे कार्यों की लंबी सूची संघ के सेवाभाव की है जो देश में आने वाली आपदाओं के वक्त देखने को मिलती है। उक्त उदाहरण उनमें से कुछ है।

कोरोना काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवाधर्म

संकट की इस घड़ी में अपने से पहले समाज को रखते हुए स्वयंसेवकों ने दिन-रात भोजन, मास्क, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, इंजेक्शन आदि राहत सामग्रियाँ बांटने में लगे रहे। यदि लॉकडाउन के समय किए गए सेवा कार्यों पर नजर डालें तो संघ के स्वयंसेवकों ने 2020 के बीच करीब 92,656 स्थानों पर 6 लाख से अधिक स्वयंसेवकों की मदद से 80,75,664 परिवारों को राशन किट, 4,50,82,540 खाने के पैकेट वितरण, 20 लाख प्रवासी मजदूरों की मदद के साथ 15,562 यूनिट रक्तदान किया। इसके अलावा लगातार ऑक्सीजन, इंजेक्शन और भी जरूरी दवाओं के लिए लगातार 24 घंटे डटे रहे। संघ का प्रकल्प सेवाभारती ने लोगों की समस्याओं का अनुमान लगाते हुए कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के फोन कॉल का जवाब देने में लगे रहे और 100 प्रतिशत समस्याओं का समाधान भी किया। इसमें विघार्थी, दैनिक मजदूर, श्रमिकों, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार आदि का सहयोग किया। कुछ उदाहरण देखने को मिले जैसे देहरादून के स्वयंसेवकों ने टोली बनाकर मोहल्ले-मोहल्ले जाकर जरूरतमंदों को मदद करने का कार्य किया। उनके कुछ सेवाकार्य इस प्रकार रहेः

गरीब बस्तियों को लिया गोद

मध्य-प्रदेश के जबलपुर, कटनी, इंदौर, भोपाल आदि अनेक शहरों में संघ के स्वयंसेवक स्वप्रेरणा से सेवा कार्यों में जुटे रहे। वहाँ उन्होंने कुछ धर्मशालाओं से बात करके जरूरतमंदों को रुकने व भोजन की व्यवस्था कराई तो कुछ गरीब बस्तियों को गोद लेकर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य किया। वहीं छात्रावास, अतिथिशालाओं में फंसे लोगों की मदद के लिए स्वयंसेवक लगातार जुटे रहे। इसी प्रकार अमृतसर शहर में संघ के स्वयंसेवकों ने उन लोगों तक राहत पहुंचायी जो लॉकडाउन के कारण आजीविका नहीं कमा पा रहे थे। स्वयंसेवकों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से उन सभी परिवारों को राशन, भोजन व अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करायीं। इसी प्रकार रोज कमाने खाने वाले ठेला, रिक्शाचलाकों आदि को भी भोजन, राशन पहुंचाने में लगे रहे।

सेवा बस्तियों में सेवाधर्म

मेरठ में एक बड़ी संख्या दैनिक मजदूरी करने वालों की है जो प्रतिदिन पैसा कमाते हैं। इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दूसरे राज्यों या शहरों से जीविका कमाने के लिए आए हैं। लॉकडाउन के कारण जरूरतमंद की कमाई भी पूरी तरह बंद हो गई थी। संकट के इस समय में वहाँ के स्थानीय स्वयंसेवकों ने सेवा बस्तियों में असहाय एवं जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट, दूध और ब्रेड आदि पहुंचाने का कार्य किया ताकि उन्हें दिक्कतों से उबार सकें।

वामपंथी गढ़ में सेवा कार्य

जिस राज्य में आए दिन संघ के कार्यकताओं को वामपंथी अपराधी तत्त्व निशाना बनाते रहे हैं, जहाँ शाखा लगाने से लेकर कार्यक्रम तक करने में बाधा खड़ी की जाती है, उस केरल में स्वयंसेवक आपदा की इस घड़ी में भी हर संभव मदद करने को तत्पर दिखे। केरल की स्वयं सेविकाओं द्वारा फेस मास्क का निर्माण करके उन्हें स्थानीय लोगों, प्रशासन और अस्पतालों में वितरण किया गया। इसके अलावा शहर, गांव और बस्तियों में जाकर स्वयंसेवकों ने इस महामारी से बचने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया। इसी प्रकार कर्नाटक, दिल्ली, मुम्बई आदि देशभर में संघ के स्वयंसेवक हर धर्म, समाज के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए दिन-रात लगे रहे। इस आपदा के समय भी संघ के कोरोना कर्मवीरों ने सबसे पहले हाथ बढ़ाकर मदद की।

कोरोना संकटकाल के दौरान संघ के विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा किए गए सेवा कार्य जो बनती रहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां-

* सुंदरनगरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्द परिषद् ने प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 500 प्रवासी परिवारों को राशन वितरण किया। इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद् द्वारा लगभग 5 टन राशन वितरण किया गया। - (पंजाब केसरी 28 — मार्च, 2020 में प्रकाशित)

* भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) संगठन ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे मजदूरों की समस्या भी उठाई, जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे, फिशरीज, स्ट्रीट वेंडर से लेकर चायबागानों में काम करने वाले, तो सरकारों ने आर्थिक मदद की। बी.एम.एस. ने लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में मजदूरों को राशन और फूड पैकेट देने की मुहिम चलाई, और दिल्ली में ही एक लाख से ज्यादा मजदूरों को राशन और भोजन उपलब्ध कराया गया। - (द क्विंट, 5 मई 2020 में प्रकाशित)

* राष्ट्रीय स्वस्यंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के संगठन ट्सेवा भारती' ने लॉकडाउन के दौरान फंसे गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए सूखे राशन की पैकिंग यूनिट शुरू कर पैकेट वितरित किए। सेवा भारती के हजारों स्वयंसेवक दिल्ली की गरीब बस्तियों में लोगों को राशन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए सेवा भारती ने एक राशन की किट तैयार की है जिसे दक्षिणी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रीज इलाके में तैयार किया गया। -

(एबीपी न्यूज, 8 अप्रैल 2020 को प्रसारित)

* इस आपदा से निपटने के लिए आर.एस.एस. ने बस्तियों में आपदा प्रबंधन टोली बनाई। साथ ही शहर भर में 317 सहायता केंद्र भी खोले। इसके माध्यम से करीब 6996 से अधिक परिवारों को खाघान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई। पुलिस, स्वच्छता प्रहरियों व चिकित्सा स्टॉफ को मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। - (जागरण समाचार पत्र, 10 अप्रैल 2020 में प्रकाशित)

* राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन भाऊ राव देवरस सेवान्यास ने गरीब और जरूरतमंदों को दोनों वक्त का भोजन कराया, जरूरतमंदों के बीच जाकर खाघ सामग्री के पैकेट, मास्क, सेनेटाइजर, दवाइयां एवं अन्य जरूरी सामग्री बांटकर लोगों को राहत पहुंचाई। - (प्रभासाक्षी, 24 अप्रैल 2020 में प्रकाशित)

* राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लखनऊ के माधव सभागार में 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया। इसके साथ ही प्रदेश में 80 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और अन्य स्कूल-कॉलेजों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया। साथ ही सामुदायिक किचन भी स्थापित किए।

- (न्यूज 18, 2 अप्रैल 2020 में प्रकाशित)

* पीलीभीत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने ट्रॉलियों के द्वारा शहर सैनिटाइजर का अभियान चलाया। सुनगढ़ी थाना चौराहा से इस अभियान का शुभारंभ हुआ। इसके बाद स्टेशन रोड बाजार, जेपी रोड, चौक बाजार, खकरा समेत अन्य स्थानों पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया। - (जागरण सामाचार पत्र, 1 मई 2020 में प्रकाशित)

* फिरोजाबाद में लॉकडाउन के बीच जयपुर से बरेली के लिए निकले सौ से अधिक मुस्लिम लोगों के लिए आरएसएस के पदाधिकारी आगे आए और उन्होंने सभी को पानी, नाश्ता और भोजन कराया। -

(पत्रिका, 30 मार्च 2020 में प्रकाशित)

* अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ के 1,500 से अधिक सदस्यों ने देश में कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने वालों के लिए फंड जुटाया। - (पी.टी.आई., वाशिंगटन)

* अमेरिका में संघ परिवार का एक हिस्सा सेवा इंटरनेशनल पिछले कई हफ्तों में देश के 28 राज्यों में राहत कार्य चला रहा है और इसके तहत 5 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक का फंड जुटाया। - (पी.टी.आई., 2020)

* कोरोना की दूसरी लहर के बीच संघ ने भोपाल में चार क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए। 70 लोगों के भर्ती करने की व्यवस्था। - (नवदुनिया, 30 अप्रैल 2021 में प्रकाशित)

* देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर तथा राधा स्वामी सत्संग परिसर में बने कोविड सेंटर में 75 से अधिक स्वयंसेवक 24 घंटे करेंगे कार्य। - (विश्व संवाद केन्द्र, 20 अप्रैल 2021)

* कोरोना आपदा की घड़ी में स्वयंसेवक संघ के कई वैचारिक संगठन, समाजसेविकाओं ने आपदा प्रबंधन समूह बनाकर काम शुरू किया। - (उज्जैन, स्वदेश, 22 अप्रैल 2021)

इस प्रकार से 94 वर्षों के दौरान संघ हमेशा देश में आने वाली आपदाओं और संकटकाल में समाज की मदद के लिए आगे आता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष हो, देश का विभाजन, बंटवारे की विभीषिका हो, पाकिस्तान, चाइना या अन्य युद्ध हों, चक्रवात, तूफान, महामारी, बाढ़, अकाल या फिर वैश्विक महामारी कोरोना हो आदि प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं में संघ के स्वयंसेवकों ने सेवा के इतिहास रचते हैं। अनेक दुर्घटनाओं आदि के समय किए गए सेवा कार्य ने संघ के विरोधियों को भी आकर्षित किया है। देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें, इस भाव को मन में रखकर स्वयंसेवक हर अवसर पर तत्पर होकर अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहता है। यही संघ संस्कार है जिसे स्वयंसेवक आजतक पालन कर रहे हैं। अनेक सेवाभाव को स्वयंसेवकों ने सिर्फ आपदाओं के समय ही प्रकट नहीं किया, बल्कि आवश्यकतानुसार समाज के विविध क्षेत्रों में स्थायी सेवा प्रकल्प भी खड़े किए हैं। निर्धन परिवारों को शिक्षा उपलब्ध कराना, चिकित्सा सुलभ कराना, स्वच्छता कार्य, छात्रावास संचालन, ब्लड बैंक खोलना, रोजगार देना इत्यादि कार्यों को करते हुए समाज के निर्माण में कार्यकर्ताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। सही मायने में स्वयंसेवक में जो सेवक है, उसका भाव ही है 'सेवा ही जीवन है'। इसी भाव के साथ संघ का समर्पित स्वयंसेवक जीवनभर समाज, देश के लिए कार्य करता रहता है। इसी प्रकार चीनी कोरोना वायरस जैसे संक्रमण में भी संघ के स्वयंसेवकों ने देशभर में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी संघ के कार्यकर्त्ता देवदूत की तरह सेवा कार्यों में लगे रहे। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वयंसेवक 'नर सेवा नारायण सेवा' के मंत्र को आत्मसात करते हुए जरूरतमंदों को हर संभव मदद दिया और इस महामारी से निपटने में समाज को सबलता प्रदान किया। आज जब हम इस महामारी के दूसरी लहर पर विजय प्राप्त करने की ओर है। इस दौरान संघ व इसके स्वयंसेवक समाज को पुनः इस महामारी की चपटे से बचाने के लिए जागरूक करने के साथ अगली लहर के प्रकोप से निपटने आपदा प्रबंधन समूह बनाकर तैयार में जुटे हैं।

संदर्भ

1. पाञ्चजन्य, 5 अप्रैल 2020, नई दिल्ली (वही) पृष्ठ, 11-14, वही पृष्ठ-15

2. पाञ्चजन्य, 26 अप्रैल 2020, नई दिल्ली (वही) पृष्ठ 34, वही पृष्ठ 42

3. पाञ्चजन्य, 10 मई 2020, नई दिल्ली (वही) पृष्ठ 6-8, वही पृष्ठ 11-13

4. अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, द्वारा आयोजित वेबीनार।

5. कृतिरूप संघ दर्शन, सेवाभाव, पुष्प 3, भाग 3, श्री भारती प्रकाशन, नागपुर, 2018

6. कृतिरूप संघ दर्शन पुस्तक माला, पुष्प-1, राष्ट्रीय एकात्मता, श्री भारती प्रकाशन नागपुर, 2018

7. कृतिरूप संघ दर्शन, पुस्तक माला, पुष्प-2, शिक्षा संस्कार, श्री भारती प्रकाशन, नागपुर, 2018

8. कृतिरूप संघ दर्शन, पुस्तक माला, पुष्प-4, गो-ग्राम रक्षा

9. कृतिरूप संघ दर्शन, पुस्तक माला, पुष्प-5, अर्थ-आयाम श्री भारती धर्म रक्षा

10. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवाकार्य, विश्व संवाद केन्द्र, संघ केन्द्रीय मीडिया केन्द्र, नई दिल्ली

11. पंजाब, पंजाब केसरी समाचार पत्र (स.प.), सुंदरनगर, 28 मार्च 2020

12. पंजाब केसरी, (स.प.), पंजाब, सुन्दरनगर, 28 मार्च 2020

13. द (वेब पोर्टल), समाचार पत्र (स.प.) बहराइच, उत्तर-प्रदेश, 29 मार्च 2020

14. पायनियर (हिन्दी पोर्टल), उत्तर-प्रदेश, 29 मार्च 2020

(लेखक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में उपनिदेशक हैं।)

वृक्ष

हमेशा पूजे जाते हैं हिंदू धर्म में

हिंदू धर्म में प्रत्येक वस्तु व प्राणी वंदनीय है।

डॉ. नीरेत्तमा मौदगिल

हरे भरे वनों में कुलांचे भरते पशु, वृक्षों की टहनियों पर फुदकते चहचहाते पक्षी, देवदूत से अड़िग खड़े पर्वत, झरनों के रूप में बहता दुग्ध धवल नीर भला किसे आनंदित नहीं करता? प्रकृति के यह रमणीय स्थल इसी धरा पर विद्यमान हैं। लेकिन अफसोस हम पढ़े लिखे लोग विकास के नाम पर विनाश करने पर तुले हैं। दरकते पर्वत, उफनती नदियां, धधकते दावानल प्रकृति के विनाश की कहानी कह रहे हैं। प्रकृति समय समय पर अपना रौद्र रुप दिखा कर मनुष्य को चेतावनी दे रही है। लेकिन मानव की स्वार्थ लोलुपता तथा अधिक और अधिक पाने की अंतहीन इच्छा ने उसे अंधा कर दिया है और वह आने पीढ़ी को अंधकारमय भविष्य की और धकेल रहा है।

हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को अपने दैनिक क्रियाकलापों के साथ ऐसे बांध रखा था कि मानव और प्रकृति को अलग करना असंभव था। सूर्य को जल अर्पण हो या तुलसी वंदन, परिवार का प्रत्येक सदस्य इसकी महत्ता समझता था तथा प्रकृति से संबंधित कार्य बड़े ही श्रद्धा भाव से किए जाते थे। इसी तरह उन्होंने पेड़ों के महत्व को पहचान कर उन्हें वंदनीय बनाया। यूं तो कण कण में भगवान मानने वाले हिन्द धर्म में प्रत्येक वस्तु व प्राणी वंदनीय है, लेकिन औषधिय महत्व को देखते हुए निम्न वृक्ष विशिष्ट रुप से पूजनीय हैं।

नीम:- घर आंगन को छांव प्रदान करता नीम का पेड़ तो मानो घर का वैद्य ही है। ज्वर होने पर कोमल पत्तियां पानी में पीस कर पिलाना और त्वचा सम्बन्धी रोग होने पर पत्तियों को पानी में उबाल कर नहलाना इसके औषधीय गुण दर्शाता है। अनाज भण्डारण में भी नीम की पत्तियां उपयोग में लाईं जाती हैं। इसकी दातुन मसूड़ों व दांतों को रोगो से बचाता है, तो मीठी निम्बोलियां रक्त शुद्धि के काम आती हैं। इसीलिए नीम एक चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। नीम को संस्कृत में निम्ब कहा जाता है। यह वृक्ष अपने औषधीय गुणों के कारण पारंपरिक इलाज में बहुपयोगी सिद्ध होता आ रहा है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।

निम्ब शीतों लघुग्राही कतुर कोअग्नी वातनुत।

अध्यः श्रमतुटकास ज्वरारुचिक्रिमी प्रणतु ॥

अर्थात नीम शीतल, हल्का, ग्राही पाक में चरपरा, हृदय को प्रिय, अग्नि, वाट, परिश्रम, तृषा, अरुचि, क्रीमी, व्रण, कफ, वामन, कोढ़ और विभिन्न प्रमेह को नष्ट करता है। नीम के पेड़ का औषधीय के साथ-साथ धार्मिक महत्त्व भी है। मां दुर्गा का रूप माने जाने वाले इस पेड़ को कहीं-कहीं नीमारी देवी भी कहते हैं और इस पेड़ की पूजा की जाती है।

वट/बरगद:- चौपाल शब्द का उच्चारण करते ही आंखों के सामने एक घने छायादार वृक्ष के नीचे बैठे गांव के बुजुर्गों का चित्र उभर कर आता है। ये बड़े बूढ़े न केवल अपने जीवन के अनुभव युवी पीढी के साथ बांटते हैं, बल्कि उन पर नजर भी रखते हैं। गाँव में किसी अपरिचित के प्रवेश करते ही उनकी आँखें चौकन्नीं हो जाती हैं। इसीलिए तो सारे गाँव की स्त्रियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करतीं हैं। बरगद का घना छायादार पेड़ वायु शुद्ध करने के साथ साथ अपने आस पास के वातावरण को शीतलता प्रदान करता है। इसकी जड़ें भूमि कटाव को रोकतीं हैं। टहनियाँ अनेक प्रकार के पक्षियों का आश्रय स्थल होने के साथ साथ गाँव भर के बालकों का क्रीड़ा स्थल भी होतीं हैं जहाँ हर परिवार के बच्चे भयमुक्त वातावरण में खेलते हैं और उनकी माताएँ निश्चिन्त हो कर अपने घर का काम निपटाती हैं।

वट सावित्री पूजा का सम्बन्ध पेड़ के अस्तित्व को बचाए रखने से है। यह पूजा सुहागिन स्त्रियों द्वारा घर की सुख शान्ति व पति की दीर्घायु हेतु की जाती है। बरगद के पेड़ की पूजा व परिक्रमा करते हुए दीपक जला कर सुख, शान्ति व समृद्धि के साथ साथ परिवार के सदस्यों की दीर्घायू का वरदान मांगा जाता है। ग्रामीण अंचल में इस वृक्ष का विशिष्ट महत्व है।

पीपल:- सभी प्राणीयों को प्राणवायु प्रदान करने वाला पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में विशेष रुप से वन्दनीय है। अन्य पेड़ों की तुलना में यह वृक्ष अधिक मात्रा में तथा दिन रात आक्सीजन प्रदान करता है। डाक्टर भी अस्थमा के मरीजों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठना की सलाह देते हैं। पीपल के प्रत्येक तत्व जैसे छाल, पत्ते, फल, बीज, दूध, जटा एवं कोपल तथा लाख सभी प्रकार की आधि-व्याधियों के निदान में काम आते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पीपल को अमृततुल्य माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फल में सब देवताओं से युक्त भगवान का अच्युत निवास है। इसीलिए पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीपल का वृक्ष विशेष रुप से वन्दनीय होने के कारण इसको काटना मना है। देखा जाए तो इस वृक्ष को कटने से बचाने के लिए ही पीपल को पूजा अर्चना के साथ जोड़ा गया है।

आंवला:- आधुनिक युग के किसी भी प्राणी से आंवला की महत्ता छिपी नहीं है। विटामिन सी से भरपूर आंवला मनुष्य को कईं रोगों से बचाने के साथ साथ चिरयुवा भी वनाए रखता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी वास करते हैं। इसलिए आंवले की पूजा करने से आरोग्यता और सुख-समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला (अक्षय) नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है।

आम:- आम का फल दुनियाभर में अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में अनुयायियों के लिए आम के वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। घर में जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं, तो मुख्य द्वार या पूजा स्थल के द्वार व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ी लगाई जाती है। धार्मिक पंडाल और मंडपों में सजावट के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ में भी आम की लकड़ी का उपयोग होता है। आम भी आरोग्यता प्रदान परने वाला फल है।

खेजड़ी/शमी:- खेजड़ी के वृक्ष का किसानों से गहरा सम्बन्ध है। यह वृक्ष सूखा पड़ने की पूर्व सूचना देता है। जिससे किसान आने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए प्रबन्ध कर लेते हैं। वराहमिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फूलता-फलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। हिंदू धर्म में शमी या खेजड़ी के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा रही है। लंका विजय से पूर्व भगवान राम द्वारा शमी

के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। वसन्त ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है।

बिल्व/बेल:- बिल्व वृक्ष की तासीर बहुत शीतल होती है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए इसके फल का शर्बत बड़ा ही लाभकारी होता है। यह शर्बत कुपचन, आंखों की रोशनी में कमी, पेट में कीड़े और लू लगने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उत्तम है।

इसकी पत्तियाँ उच्च रक्तचाप में पयोगी होती हैं। औषधीय गुणों से परिपूर्ण बिल्व की पत्तियों मे टैनिन, लोह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नेशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियाँ समाहित हिन्द धर्म में इसे भगवान शिव का रूप ही माना जाता है।

अशोक:- अशोक का वृक्ष वात-पित्त आदि दोष, अपच, तृषा, दाह, कृमि, शोथ, विष तथा रक्त विकार नष्ट करने वाला है। यह रसायन और उत्तेजक है। इसके उपयोग से चर्म रोग भी दूर होता है। अशोक का वृक्ष घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचारण बना रहता है। हिन्द धर्म में अशोक वृक्ष को पवित्र और लाभकारी माना गया है। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि अशोक वृक्ष घर में लगाने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है।

अशोक का वृक्ष दो प्रकार का होता है-एक तो असली अशोक वृक्ष और दूसरा उससे मिलता-जुलता नकली अशोक वृक्ष। नकली अशोक वृक्ष देवदार की जाति का लंबा वृक्ष होता है। असली अशोक का वृक्ष आम के पेड़ जैसा छायादार वृक्ष होता है। सुनहरे लाल रंग के फूलों वाला होने से इसे 'हेमपुष्पा' भी कहा जाता है।

नारियल का वृक्ष:- नारियल हिंदू धर्म के सभी पूजा-पाठ का महत्वपूर्ण अंग है। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। इस वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी काम में आता है। ये वृक्ष किसानों के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनसे घरों के पाट, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। पत्तों से पंखे, टोकरियां, चटाइयां आदि बनती हैं। इसकी जटा से रस्सी, चटाइयां, ब्रश, जाल, थैले आदि अनेक वस्तुएं बनती हैं। यह गद्दों में भी भरा जाता है। नारियल का तेल सबसे ज्यादा बिकता है।

नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। अगर आप पाचन की समस्या में भी नारयिल पानी बहुत लाभप्रद है। नारियल के गूदे का इस्तेमाल नाड़ियों की समस्या, कमजोरी, स्मृति नाश, पल्मनरी अफेक्शन्स (फेफड़ों के रोगों) के उपचार के लिए किया जाता है। यह त्वचा संबंधी तथा आंतड़ियों संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को भी नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है।

केला/कदली:- केले का पेड़ हिन्द धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और धार्मिक कार्यों में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य व मांस बढ़ाने वाला, नेत्रदोष में हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन से शरीर पुष्ट होता है। यह कफ, रक्तपित, वात और प्रदर के उपद्रवों को नष्ट करता है।

अनार/दाड़िम:- पूजा के दौरान पंच फलों में अनार को भी शामिल किया जाता है। मान्यता है कि अनार के वृक्ष से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता हैं। जहाँ इस वृक्ष के फल, फूल व कलियाँ देखने में बहुत सुन्दर होते हैं वहीं इस वृक्ष के कई औषधीय गुण भी हैं। अनार का प्रयोग करने से खून की मात्रा बढ़ती है। इससे त्वचा सुंदर व स्निग्ध होती है। प्रतिदिन अनार खाने से त्वचा का रंग निखरता है।

अनार के छिलकों के एक चम्मच चूर्ण को कच्चे दूध और गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा दमक उठता है। अपच, दस्त, पेचिश, दमा, खांसी, मुंह में दुर्गंध आदि रोगों में अनार लाभदायक है। इसके सेवन से शरीर में झुर्रियां या मांस का ढीलापन समाप्त हो जाता है।

वृक्षों का महत्व जानने वाले हमारे पूर्वजों ने वृक्षों का महत्व देखते हुए इन्हें पूजा पाठ व त्योहारों के साथ जोड़ दिया, ताकि कालान्तर में इनकी रक्षा की जा सके। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, दस इमली, तीन कैथ, तीन बेल, तीन आंवला और पांच आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता।

नवग्रह वाटिका

पौधे लगाते समय विभिन्न कोणों का भी ध्यान रखा गया है।

पर्यावरण गतिविधि टीम

ग्रह: पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर आसमान में स्थिर दिखने वाले पिंड़ों/छायाओं को नक्षत्र और स्थिति बदलते रहने वाले पिंड़ों/ छायाओं को ग्रह कहते कहते हैं। ग्रह का अर्थ है पकड़ना। संभवत: अंतरिक्ष से आने वाले प्रवाहों को धरती पर पहुंचने से पहले ये पिंड और छायाएं उन्हें टीवी के एंटीना की तरह आकर्षित कर पकड़ लेती हैं और पृथ्वी के जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन्हें ग्रह कहा गया है और बहुत महत्त्व दिया गया है।

नवग्रह वाटिका व्याख्या

नवग्रह: भारतीय ज्योतिष मान्यता में ग्रहों की संख्या 6 मानी गई है, जैसा निम्र श्लोक में वर्णित है-

सूय्र्यचन्द्रो मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति:।

शुक्र: शनेश्चरो राहु: केतुश्चेति नव ग्रहा:।।

अर्थात् सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह हैं। इनमें प्रथम 7 तो पिंडीय ग्रह हैं और अंतिम दो राहु और केतु पिंड रूप में नहीं हैं, बल्कि छाया ग्रह हैं।

ग्रह शांति: ऐसी मान्यता है कि इन ग्रहों की विभिन्न नक्षत्रों में स्थिति का विभिन्न मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों के शमन के अनेक उपाय बताये गये हैं, जिनमें एक उपाय यज्ञ भी है।

पमिधायें: यज्ञ द्वारा ग्रह शांति के उपाय में हर ग्रह के लिए अलग अलग विशिष्ट वनस्पति की समिधा (हवन प्रकाष्ठ) प्रयोग की जाती है, जैसा निम्न श्लोक में वर्णित है-

अर्क: पलाश: खदिरश्चापामार्गोऽथ पिप्पल:।

औडम्बर: शमी दूव्र्वा कुशश्च समिध: क्रमात्।।

अर्थात अर्क (मदार), पलाश, खदिर (खैर), अपामार्ग (लटजीरा), पीपल, ओड़म्बर (गूलर), शमी, दूब और कुश क्रमश: (नवग्रहों की) समिधायें हैं।

ग्रह अनुसार वनस्पतियों की सूची

इस तरह ग्रह अनुसार वनस्पतियों की सूची निम्न प्रकार है-

सूर्य - अर्क (आक)

चन्द्र - पलाश (ढाक)

मंगल - खादिर (खैर)

बुध - अपामार्ग (लटजीरा)

बृहस्पति - पिप्पल (पीपल)

शुक्र - औड बर (गूलर)

शनि - शमी (छयोकर)

राहु - दूर्वा (दूब)

केतु - कुश (कुश)

ग्रह शांति के यज्ञीय कार्यों में सही पहचान के अभाव में अधिकतर लोगों को सही वनस्पति नहीं मिल पाती, इसलिए नवग्रह वृक्षों को धार्मिक स्थलों के पास रोपित करना चाहिए, ताकि यज्ञ कार्य के लिए लोगों को शुद्ध सामग्री मिल सके। यही नहीं, यह विश्वास किया जाता है कि पूजा–अर्चना के लिए इन वृक्ष वनस्पतियों के संपर्क में आने पर भी ग्रहों के कुप्रभावों की शांति होती है, अतः नवग्रह वनस्पतियों के रोपण की महत्ता और बढ़ जाती है।

ग्रहों से संबंधित वृक्ष इस प्रकार हैं...

सूर्य - मंदार

चन्द्र - पलाश

मंगल - खैर

बुध - लटजीरा, आँधीझाड़ा

गुरु - पारस पीपल

शुक्र - गूलर

शनि – शमी

राहु-केतु - दूब चन्दन

नक्षत्र वृक्षों की तालिका

अश्विनी - कुचिला

भरणी - आमला

कृत्तिका - गूलर

रोहिणी - जामुन

मृगशिरा - खैर

आर्द्रा - शीशम

पुनर्वसु - बाँस

पुष्य - पीपल

आश्लेषा - नागकेशर

मघा - बरगद

पूर्व फाल्गुनी - पलाश

उत्तर फाल्गुनी - पाठड़

हस्त - अरीठा

चित्रा - बेलपत्र

स्वाती - अर्जुन

विशाखा - कटाई

अनुराधा - मौल श्री

ज्येष्ठा - चीड़

मूल - साल

पूर्वाषाढ़ा - जलवन्त

उत्तराषाढ़ा - कटहल

श्रवण - मंदार

घनिष्ठा - शमी

शतभिषा - कदम्ब

पूर्वभाद्रपद - आम

उत्तरभाद्रपद - नीम

रेवती - महुआ

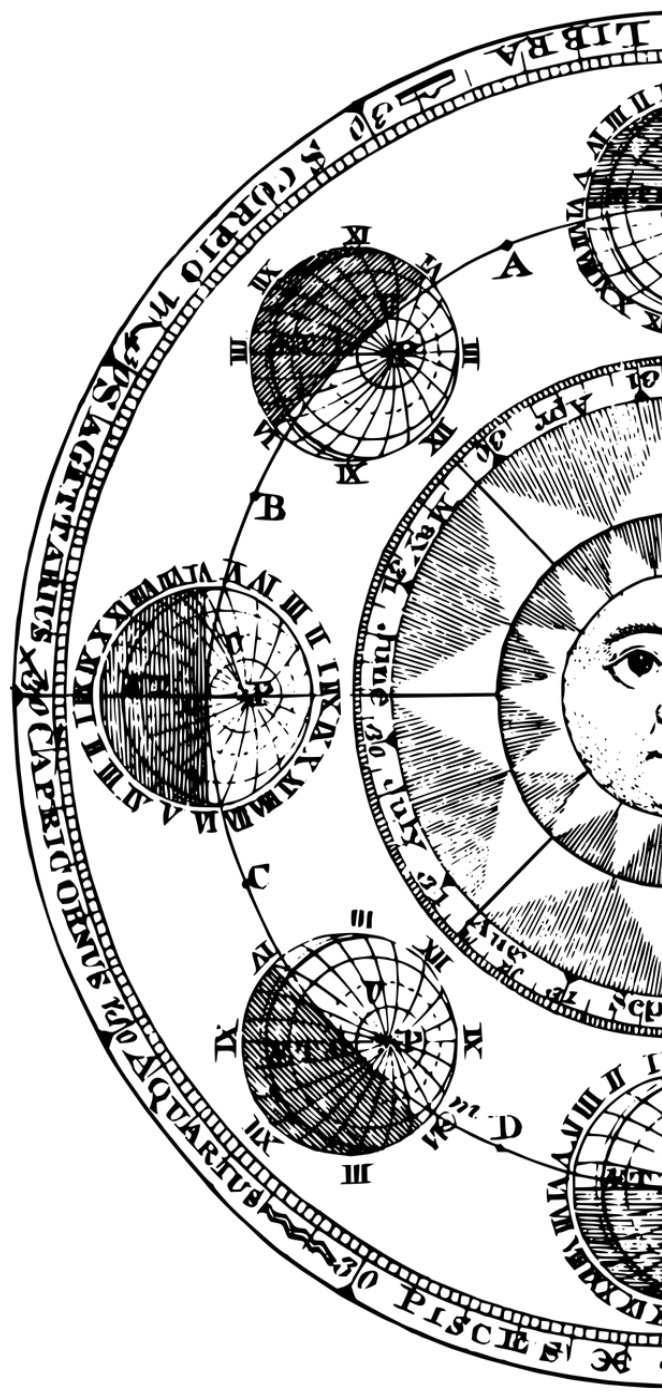

नवग्रह वाटिका में पौधे लगाते समय विभिन्न कोणों का भी ध्यान रखा गया है। उत्तर दिशा में पीपल, ईशान कोण में लटजीरा, पूर्व में गूलर, आग्नेय कोण में ढाक व दक्षिण में खैर लगाया गया है। ध्यान रखें की पीपल के वृक्ष का प्रयोग क्षय रोग व गर्भस्राव में, गूलर घावों को भरने व मूत्ररोगों में, खदिर त्वचा संबंधी रोगों में व पलाश पेट के कीड़ों को दूर करने में प्रयुक्त होता है। अलग-अलग नौ ग्रहों के अनुसार नवग्रह वाटिका में अलग-अलग पेड़-पौधे लगाये जाते हैं, जिसका ज्योतिषीय प्रभाव अलग-अलग होगा। वहीं संबंधित ग्रह के शमन के लिए लोग उससे संबंधित पेड़-पौधों का उपयोग व आनंद प्राप्त कर सकेंगे। इसमें सूर्य के लिए मंदार का पौधा लगाया जायेगा। चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुद्ध के लिए चिरचिरी, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गुलड़, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दुर्वा व केतु के लिए कुश लगाया जायेगा।

पर्यावरण संरक्षण

कुड़ी गांव का कमाल

विद्यार्थियों के अथक प्रयास से आज वृक्षविहीन पहाड़ी हुई हरीभरी।

जोधपुर के एक गांव कुड़ी (भोपालगढ़) का विद्यालय, जहां स्वयंसेवक शिक्षक लालाराम जी भाटी कार्यरत थे। लालाराम जी की प्रेरणा से विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। लालाराम जी का स्थानान्तरण हो गया, परन्तु विद्यार्थियों के हृदय में पर्यावरण संरक्षण का भाव अंकुरित हो चुका था। महेंद्र सिंह, गणपतराय, छोटाराम, सीताराम, तेजाराम, जयराम, दिनेश, रामभरोसे, श्रवण, राकेश एवं महंत भंवरनाथ ने मिलकर गांव में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी के कायाकल्प की योजना बनाई। पहाड़ी पर नाथ पंथ के संत सुजाननाथ की तपोस्थली है, जो कि सम्पूर्ण ग्रामवासियों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। संत के प्रति श्रद्धा इतनी है कि प्रत्येक ग्रामवासी जातिगत भेदभाव के अभाव में सभी मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम संत की पूजा करते हैं।

विद्यार्थियों ने इसी पहाड़ी पर बैठकर अपने कार्य का शुभारम्भ किया। धन की आवश्यकता के रूप में प्रथम समस्या का सामना हुआ। इसके समाधान के रूप में तत्काल श्री सुजाननाथ सेवा समिति के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया एवं उसमे पहाड़ी के कायाकल्प के लिए सहयोग की प्रार्थना की गयी। 10-15 दिवस में ही सहयोग राशि के रूप में दो लाख आठ हजार पांच सौ इकसठ रूपये एकत्र हो गए। शुभ मुहूर्त में जेसीबी से खड्डा खुदवाकर कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात उसमें रेत भरवाई गयी। गाँव की अन्य युवा शक्ति को भी जोड़ा गया। सभी ने श्रमदान किया और वृक्षविहीन पहाड़ी पर दो सौ इक्कीस पौधे ट्री गार्ड सहित लगाये गए। विद्यार्थियों सहित गांव की अन्य युवा शक्ति ने वर्षभर देखभाल की। पूरे वर्ष में मात्र चार पौधे नष्ट हुए, जिनके स्थान पर पुनः दूसरे पौधे लगाये गए।

वृक्षविहीन पहाड़ी पर दो सौ इक्कीस पौधे ट्री गार्ड सहित लगाये गए। विद्यार्थियों सहित गांव की अन्य युवा शक्ति ने वर्षभर देखभाल की। पूरे वर्ष में मात्र चार पौधे नष्ट हुए, जिनके स्थान पर पुनः दूसरे पौधे लगाये गए।

अगले वर्ष अर्थात 14 जून 2021 को इन पौधों की वर्षगांठ का भव्य उत्सव रखा गया, जिसमे रात्रि जागरण के पश्चात् सम्पूर्ण ग्रामवासियों के लिए प्रसादी का कार्यक्रम हुआ। ब्लड डोनेशन कैम्प में 79 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ। भामाशाहों एवं रक्तदाताओं को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य पर चार लाख इकत्तीस हजार रूपये एकत्र हुए तथा एक सौ इक्कीस पौधे और लगाये गए। सम्पूर्ण वर्षा ऋतु में पौधरोपण का कार्य अनवरत चलता रहेगा। धन के सदुपयोग के लिए वित्त समिति के द्वारा खर्च का सम्पूर्ण हिसाब रखा जाता है। पहाड़ी पर जल की समस्या के समाधान के रूप में एक पर्यावरण प्रेमी श्री लुम्बा राम जी भाटी ने ट्यूबवेल खुदवाई, जिसकी लागत दो लाख तीस हजार रूपये आई। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नीलगाय तथा जंगली सूअरों से पौधों पर निरंतर संकट की स्थिति थी, इसलिए इस वर्ष पहाड़ी के चारों ओर पत्थर की दीवार करवाई गयी। विद्यार्थियों के अथक प्रयासों से आज वृक्षविहीन पहाड़ी दूर से ही हरी भरी दिखाई देती है।

पर्यावरण
PERSPECTIVE

Contact Us At:
9449802157
sanrakshanparyavaran@gmail.com

Don’t forget to visit

WWW.PARYAVARANPERSPECTIVE.COM